A Daily News Magazine
इंदौर
सोमवार, 29 जून, 2026

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 11 अंक 267, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

कच्चे तेल की घटी कीमत का लाभ आम उपभोक्ता को कब मिलेगा ?

संदीप राय

तेल की क़ीमतें ईरान जंग शुरू होने से पहले के स्तर पर लौट आई हैं और माना जा रहा है कि इससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक भारत को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। गुरुवार को वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड कुछ समय के लिए 72.48 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। यह वही स्तर था, जो 28 फ़रवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले शुरू करने से एक दिन पहले था। शुक्रवार को तेल की क़ीमतें और घटकर 72.60 डॉलर प्रति बैरल हो गईं। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद से कच्चे तेल की क़ीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और बाज़ार के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में तेल के दामों और गिरावट आ सकती है। ग़ौरतलब है कि ईरान जंग के दौरान तेल की क़ीमतों में 120 डॉलर प्रति बैरल तक उछाल आ गया था। लेकिन कच्चे तेल की क़ीमतों में तेज़ गिरावट के बावजूद भारत में खुदरा ईंधन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि हाल में अंतरराष्ट्रीय तेल क़ीमतों में उछाल के दौरान पेट्रोल और डीज़ल के दामों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। दामों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी को भी कम किया था।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी क्षेत्र की तीनों कंपनियां इस समय पेट्रोल की बिक्री पर अच्छा मार्केटिंग मार्जिन कमा रही हैं, जबकि डीज़ल की बिक्री पर अभी भी मामूली घाटा हो रहा है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि कच्चे तेल की हालिया गिरावट का फ़ायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। '

बाज़ार विश्लेषकों ने कहा कि किसी भी राहत के लिए भारतीय उपभोक्ताओं को दो से ढाई महीने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है और वो भी तब जब ऊर्जा बाज़ार इसी तरह अधिक से अधिक स्थिर होता जाए। मनी कंट्रोल के मुताबिक़, संघर्ष शुरू होने के बाद शुरू की गई अंतर-मंत्रालयी ब्रीफ़िंग को फ़िलहाल चुपचाप रोक दिया गया है, जो यह संकेत देता है कि ऊर्जा आपूर्ति में तत्काल व्यवधान को लेकर चिंता कम हुई है।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक़, भारत जो कच्चा तेल ख़रीदता है, उसका औसत दाम बीते 27 फ़रवरी को 71.17 डॉलर प्रति बैरल था। इसके दूसरे दिन यानी 28 फ़रवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था।

पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक़, 24 जून को भारतीय बास्केट का औसत दाम 70.71 डॉलर प्रति बैरल रहा। पीपीएसी के अनुसार, पूरे जून महीने में भारतीय बास्केट का औसत दाम 86.31 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि फ़रवरी 2026 में यह औसत 72.47 डॉलर प्रति बैरल था।

हालांकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के निदेशक अजय श्रीवास्तव ने इस बास्केट प्राइस को भी अधिक बताया। भारत सरकार को इस बारे में कोई रणनीति बनानी चाहिए।

ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू के बाद अमेरिका ने ईरान के तेल से 60 दिन के लिए प्रतिबंध हटा लिया है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अब ईरानी तेल के भी भारतीय बास्केट में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में ईंधन कंपनियों और सरकार पर उपभोक्ताओं को राहत देने का दबाव बढ़ सकता है, ख़ासतौर पर तब जब कच्चे तेल की क़ीमतें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं। ईंधन के कम दाम भारत के ऑयल बिल को कम कर सकते हैं, और चालू खाते का घाटा भी कम हो सकता है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय क़ीमतों में कमी का भारतीय उपभोक्ताओं को तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि इससे ऊर्जा सब्सिडी का बोझ भी कम हो सकता है और सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने कहा कि सितंबर से पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन के दाम कम होने की संभावना नहीं है। आज जो दाम हैं उस आधार पर ख़रीदे गए ईंधन को भारत पहुंचने में हफ़्ते भर से दो महीने तक का समय लग सकता है। क्योंकि अभी वो तेल आ रहा है जिसे महंगे दामों पर ख़रीदा गया था। अभी भारत 40 अलग-अलग देशों से तेल आयात करता है। अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील से तेल भारत आने में क़रीब दो महीने और रूस से एक महीना लग जाता है।

दरअसल भारत अपनी कुल ज़रूरत का 88 फ़ीसदी से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। नरेंद्र तनेजा का कहना है कि विदेशों से आयात होने से लेकर भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक चक्र क़रीब ढाई महीने का होता है। पहले सऊदी अरब जैसे देशों से तेल आता था तो यह चक्र छोटा होता था। आज जो तेल पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है उसे भारतीय कंपनियों ने ढाई महीने पहले 110 से 130 डॉलर प्रति बैरल की दर से ख़रीदा था। मेरे हिसाब से सितम्बर तक सस्ता तेल आएगा, तब तक कंपनियां अपना कुछ घाटा भी पूरा कर चुकी होंगी और उस समय तीज त्योहार का मौसम भी शुरू हो चुका होगा। तब सरकार ईंधन के दामों में कुछ राहत दे सकती है। लेकिन ये आकलन इस धारणा पर आधारित है कि ईरान और अमेरिका के बीच सबकुछ ठीक चलेगा।

जीटीआरआई के निदेशक अजय श्रीवास्तव ने कहा, 'कच्चे तेल के दाम और पंप पर मिलने वाले तेल के दाम में कोई संबंध नहीं है। जब क्रूड के दाम कम होते हैं तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है। आज ज़रूरत है कि सरकार एक पारदर्शी सिस्टम ले आए और बताए कि बास्केट प्राइस के मुक़बले जो पंप पर तेल मिलता है उसमें रिफ़ाइनिंग और वितरण कंपनियों को कितना प्रतिशत मिलता है और राज्य-केंद्र सरकारों के टैक्स का कितना प्रतिशत है।' अजय श्रीवास्तव ने बताया, 'साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज़्म को ख़त्म करके तेल की क़ीमतों को डीरेगुलेट किया था और यह सिस्टम 2016-17 तक चला लेकिन उसके बाद सरकारों ने टैक्स बढ़ा कर तेल की क़ीमतों को नियंत्रित किया।'

मौजूदा हालात में तेल की क़ीमतों को कम करने को लेकर वो कहते हैं, 'कुछ कहा नहीं जा सकता कि दाम कम होंगे या नहीं। सबकुछ सरकार के हाथ में है। और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। '

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

प्रधानमंत्री मोदी को मिला सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान

विक्टोरिया (एजेंसी)। पीएम मोदी ने शनिवार को भारत में निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) पीएस लेस्पवार को सेशेल्स को सौंप दिया। रविवार को राजधानी विक्टोरिया पहुंचने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ

- **गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया**

विकास में उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को सेशेल्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और सेशेल्स की राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग, कोस्ट गार्ड और समुद्री निगरानी समेत कई समझौते हो सकते हैं।

पीएम मोदी ने सौंपा मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे। शनिवार को पीएम मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स कोस्ट गार्ड बेस पर आयोजित समारोह में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी को पेट्रोल वेसल सौंपा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस खास पेट्रोल वेसल से सेशेल्स की समुद्री निगरानी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त करने की क्षमता मजबूत होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सेशेल्स कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल लेस्पवार सौंपना, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और सेशेल्स के बीच बढ़ती साझेदारी में अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है।

ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा : ट्रंप

फिर से दी धमकी, ईरान ने भी किया पलटवार

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। यह कार्रवाई 'एम/टी किकु' नाम के तेल टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। दूसरी ओर, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।

खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां

ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए उनके पार्थिव शरीर को सड़क के बजाय हेलीकॉप्टर या सैन्य विमान से ले जाने पर विचार किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इराक की राजधानी बगदाद में इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अल जजीरा के मुताबिक, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए इराक के धार्मिक स्थलों पर आपसी समन्वय पर भी बातचीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुआद हुसैन ने कहा, क्षेत्र में युद्ध अभी भी दूसरे रूप में जारी है।

सुप्रभात

तुम्हारे नाम की हो रही है लूट
हे राम !
तुम्हारे नाम को जप रहा है झूठ
हे राम !
तुम्हारे नाम से भर रहे हैं पेट
हे राम !
तुम्हारे नाम पर ठग रहे हैं सेठ
हे राम !
तुम्हारे नाम पर सजे हुए हैं बाज़ार
हे राम !
तुम्हारे नाम पर जम गया है व्यापार
हे राम !
तुम्हारे नाम पर डाकू भी सन्त
हे राम !
तुम्हारे नाम की महिमा है अनन्त
हे राम !

– रामकुमार कृषक

कुकरू की वादियों में सीएम ने किया योग, बुवाई भी की

रुद्राक्ष का पौधा रोपकर दिया स्वस्थ जीवन का बड़ा संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू में अपने दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन की शुरुआत योगाभ्यास से की। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ विभिन्न योगासन किए और सभी से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कुकरू के कॉफी बागान का निरीक्षण कर वहां की संभावनाओं की भी जानकारी ली और खेत में किसान के साथ बुवाई की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योगाभ्यास के दौरान मयूरासन, शीर्षासन सहित कई कठिन योगासन कर अपनी फिटनेस का परिचय दिया। उन्होंने ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वक्रासन, भुजंगासन और शलभासन जैसे आसनों का अभ्यास स्थानीय ग्रामीणों के साथ किया। इसके अलावा नाड़ी शोधन, तितली और भ्रामरी प्राणायाम भी किए गए। योग कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य मंगल सिंह धुर्वे, बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे।

योग से मिलता है संतुलन और ऊर्जा : सीएम

योगाभ्यास के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैतूल के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योग करना सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वस्थ और सशक्त जीवन के लिए योग को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आग्रह किया।

राममंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस का ऐक्शन

8 आरोपियों के घर आठ टीमों की एक साथ छापेमारी

अयोध्या (एजेंसी)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों के घर पर रविवार सुबह 7 बजे पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ, एक ही वक्त पर आरोपियों के घर पर दबिश दी। इस दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा था। पुलिस ने पड़ोसियों से सवाल-जवाब किए। छापेमारी के दौरान चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर पर ताला लगा मिला। कुछ देर बाद टिन्नू की मां मौके पर पहुंचीं और ताला खोला। पुलिस ने अंदर जांच पड़ताल की। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर भतीजे आरोपी मनीष यादव के घर पहुंची तो वहां भी ताला लगा था। वहीं, आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी ताला लगा मिला। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी हुई। खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक अकाउंट डिटेल खंगाले गए। परिजनों के बयान दर्ज किए गए।

छापेमारी में राजस्व अधिकारियों खासकर लेखपालों को शामिल किया गया। संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा- एसआईटी मामले की जांच कर रही है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अयोध्या का राम राज्य ऐसा है कि अपराधियों को कभी माफ नहीं किया जाता। उन्हें सजा दी जाती है।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को तीन दिन के लिए जेल भेजा

FIR दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को तीन दिन के लिए जेल भेज दिया। शुक्रवार को ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा- एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। सरकार, ट्रस्ट और संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसलिए, देश को राजा, संगठन और ट्रस्ट पर भरोसा है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो अयोध्या का राम राज्य ऐसा है कि अपराधियों को कभी माफ नहीं किया जाता।

15 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी

अगस्त से पहला बैच शुरू होगा, विदेश जैसी ही डिग्री मिलेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में अब विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार अब तक

15 विदेशी विश्व विद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुकी है। इनमें ज्यादातर कैंपस अगस्त से पहला बैच शुरू करेंगे। शुरुआती चरण में हर कैंपस में 200 से 250 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। अगले पांच सालों में इसे बढ़ाकर हर कैंपस में सालाना 1,000 से 1,200 छात्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ब्रिस्टल, यॉर्क, इलिनोइस टेक, लिवरपूल और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अपने कैंपस खोल रहे हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20°c

न्यूनतम 18°c

2

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 29 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

प्रदेश की चार कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर, छत्रिय धान को मिला जीआई टैग

अब मिलेगी वैश्विक पहचान, किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए संकल्पित है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

भोपाल। प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष के चलते जब किसानों की समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मध्य प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मध्यप्रदेश की चार कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर एवं छत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। महाकौशल के किसानों ने प्रसन्नता जाहिर की है। इन कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए संकल्पित है। उनकी आय दोगुनी करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जैविक, प्राकृतिक एवं परंपरागत खेती के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मार्गदर्शन एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के सहयोग तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रयासों से प्रदेश की चार विशिष्ट कृषि उपजों–सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर एवं छत्रिय धान–को भौगोलिक संकेतक मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। जीआई टैग मिलने से इन कृषि उपजों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। उनकी ब्रांड वैल्यू एवं बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी तथा किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ कृषि निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

ये चारों कृषि उपजें प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित हैं। इससे विशेष रूप से महाकौशल क्षेत्र के किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा। इन उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्षेत्र की पारंपरिक कृषि पद्धतियों एवं जैव-विविधता का संरक्षण होगा तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात को गति मिलेगी।

पूर्व सीहोर शरबती गेहूं एवं रीवा सुन्दरजा आम को जीआई टैग दिलाने में किसान कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सिताही कुटकी- सिताही कुटकी एक कम अवधि (60 दिन) वाली 'लिटिल मिलेट' (छोटी बाजरा) की देशी किस्म है। यह वर्षा-आधारित क्षेत्रों और देर से बुवाई की स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह सूखे की मार, नमी की कमी, और प्रमुख कीटों (शूट फ्लाई), 'ग्रेन स्मट' व 'ब्राउन स्पॉट' जैसी बीमारियों का सामना करने में सक्षम है। इस प्रकार, यह किसानों को एक स्थिर पैदावार दिलाने में मददगार साबित होती है। सिताही कुटकी की मध्यम ऊँचाई और मोटे तने के कारण फसल के गिरने की समस्या नहीं रहती। इसे पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ तथा कमज़ोर मिट्टी वाली स्थितियों में भी उगाया जा सकता है। डिण्डोरी के 'बैगा' तथा 'गोंड' जनजातियों के किसानों के लिए अच्छी आय दे सकती है।

डिंडोरी में 'सिताही कुटकी' की खेती की 10,395 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी और 10-11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की स्थिर पैदावार से इस क्षेत्र में लोगों की आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा में मदद मिली है। जनजातीय ज़िलों के लगभग 60,000 आदिवासी किसान–खासकर डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, बालाघाट और जबलपुर के कुछ हिस्सों के किसान पैदावार बढ़ाकर आर्थिक लें सकते हैं। डिंडोरी के पहाड़ी और मुश्किल इलाकों के 54 गाँवों के किसानों को मुनाफ़ा हुआ है। इन इलाकों में दूसरी रबी फ़सलों की खेती नहीं होती।

नागदमन कुटकी- नागदमन कुटकी डिंडोरी जिले में उगाई जाने वाली कुटकी की एक विशिष्ट स्थानीय किस्म है। यह अपने औषधीय गुणों और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है।

बैंगनी अरहर दरअसल अरहर की विशेष किस्म है। इसमें पौधे या फलियों पर बेंगनी रंग की झलक होती है। इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। रोगों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। अच्छी देखभाल होने पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है।

संक्षिप्त समाचार

लंदन में पढ़ाई के लिए गए भारतीय छात्र की मौत

- कुछ घंटे पहले ही बर्थडे पार्टी में हुआ था शामिल

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए गए 25 साल के भारतीय छात्र की मौत हो गई है। तेलंगाना के एस श्रीनाथ रेड्डी इस हफ्ते की शुरुआत में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। उसके अगले ही दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। श्रीनाथ के परिवार ने बताया कि वे 14 महीने पहले उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे।

परिवार ने शव वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। श्रीनाथ रेड्डी तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के तालमडला गांव के रहने वाले थे। श्रीनाथ रेड्डी के पिता मधुसूदन रेड्डी ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि उनका बेटा 14 महीने पहले लंदन गया था। श्रीनाथ लीसेस्टर की डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे।

बिहार के लिए बना पन्द्रह हजार करोड़ का रोड प्लान

- 8600 करोड़ से चमकेगा राम-जानकी मार्ग, बेतिया-समस्तीपुर की भी लॉटरी

पटना (एजेंसी)। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को एक नया विस्तार मिलने जा रहा है। सम्राट सरकार ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूरी के लिए भेजी है,

जबकि कुछ अन्य प्रस्ताव जल्द ही भेजे जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के अनुसार, दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही इन सभी बड़ी परियोजनाओं पर धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इन योजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ अंतर-जिला कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि कई प्रमुख शहरों को भीषण ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।

राम मंदिर की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलाओ

- सपा प्रमुख अखिलेश को सीएम योगी की चुनौती, जमकर सुनाया

हाथरस (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हाथरस के सलेमुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वह कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखिए राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी। सीएम योगी ने कहा कि भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था।

सिया-चेतन के सामने केतन मर्डर का सीन रीक्रिएट

पुलिस दोनों को लोहागढ़ किले ले गई, दीवार से डमी गिराकर देखा

पुणे (एजेंसी)। पुणे मर्डर केस में पुलिस ने रविवार को केतन को लोहागढ़ किले से गिराने का सीन रीक्रिएट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए पुलिस सुबह 6.30 बजे दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले लेकर पहुंची। टीम करीब 2.30 घंटे किले पर रही। डीएसपी गजानन टोंपे ने कहा-आज सुबह हम सिया गोयल को घटनास्थल पर लेकर आए। उसके बताए अनुसार पूरे घटनाक्रम का सीन रीक्रिएशन किया। इसके लिए केतन के समान वजन का एक डमी तैयार किया गया, ताकि घटना को उसी तरह दोहराकर जांच की जा सके। इस बीच केस में पुलिस ने नया खुलासा किया कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने गूगल पर लोहगढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की भी जानकारी जुटाई थी।

चेतन ने की थी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश

पुलिस ने कहा- दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारें, ताकि पुलिस को शक न हो जैसे सवाल सर्च किए। पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं, यह भी खोजा। कौन-कौन से वॉट्सएप मैसेज डिलीट करना है, यह भी सर्च किया था। पुलिस ने बताया कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मर्डर के दिन अपना मोबाइल एक दुकान पर छोड़ दिया था।

सिया और चेतन को फांसी की सजा मिले

शनिवार शाम केतन अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पिंपरी-चिंचवाड़ में परिवार और सोसाइटी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, 'मेरा 26 साल का बेटा बिना किसी गलती के मारा गया। मैं उसकी शादी कराने निकला था, लेकिन बेटे की अर्थी उठानी पड़ी। मेरी सिर्फ एक मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा मिले।' केतन की मां राखी अग्रवाल ने कहा, 'मैं एक मां हूं और सिया की भी मां है।

सिया-चेतन का नया वीडियो

सिया और चेतन का नया वीडियो सामने आया। इसमें दोनों महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो कब का है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं, पुलिस की पूछताछ में सिया के भाई साहिल ने खुलासा किया कि सिया-चेतन की मुलाकात क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। इसके बाद एक दोस्त के घर दिवाली की पूजा में भी दोनों मिले थे। साहिल भी चेतन को जानता है। दरअसल, सिया और केतन 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हुई थी। सिया पर बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मंगेतर की हत्या का आरोप है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।

पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला

कराची में 4 सुरक्षाकर्मियों और 6 आतंकियों की मौत

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के कराची में शनिवार रात आतंकियों ने सिंध रेंजर्स के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। हमला रात करीब 8.30 बजे गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में हुआ। इसमें चार रेंजर्स की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में छह आतंकी मारे गए, जबकि एक आतंकी को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी के मुताबिक, आतंकी गाड़ी से मैन गेट तोड़ते हुए परिसर में घुसे।

इसके बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई धमाके हुए। करीब 90 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, एंटी टेररिस्ट फोर्स और रेंजर्स ने सभी हमलावरों को काबू कर लिया।

इलाके की घेराबंदी, लोगों को घरों में रहने की सलाह

हमले के बाद पूरे परिसर और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं और लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई। ऑपरेशन के दौरान आसपास के कुछ इलाकों में बिजली भी बाधित रही।

पीएम मोदी बोले–योग में भारत ने 114 पदक जीते

समुद्र से आकाश तक भारत हर तरह से सुरक्षित

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 135वें एपिसोड में कहा, भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने कहा- जून के महीने में ही देश ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। मेड इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किए गए सी-295 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। वर्तमान में ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के कई कार्यक्रम हुए। भारत ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 मेडल जीते हैं।

मन की बात में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का जिक्र

शादी के लिए सोना रीसाइकल कर रहे लोग पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बीते दिनों लोगों से कुछ समय तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने या कार पूलिंग की अपील की थी मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसमें सहयोग कर रहे हैं। कई परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत हुई तो वे पुराने सोने को ही रिसाइकल करेंगे।

असम-हरगिला आर्मी ने पुरानी सोच बदली

पीएम मोदी ने कहा कि असम में एक पक्षी पाया जाता है। उसका नाम हरगिला है। हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोसले बने होते थे। इसी दौरान जीव-वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया।

उपचुनाव से ठीक पहले स्टालिन को झटका

चेन्नई (एजेंसी)। वाइको के नेतृत्व वाली मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) ने शनिवार को द्रमुक नीत सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि द्रमुक ने विधानसभा चुनाव के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार बनवाने की कोशिश की, जिससे गठबंधन की वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े हो गए। एमडीएमके प्रमुख वाइको ने कहा कि उनकी पार्टी अब विधानसभा उपचुनावों में सत्तारूढ़ टीवीके का समर्थन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निकाय चुनावों में भी पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसकी सराहना करेंगे और गलतियों पर सवाल भी उठाएंगे। वाइको ने द्रमुक पर 2026 के विधानसभा चुनाव में एमडीएमके उम्मीदवारों को द्रमुक के उगते सूरज चुनाव चिह्न पर लड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अन्य सहयोगी दलों–वीसीके, आइयूएमएल और वामपंथी दलों–पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की राजनीति स्वस्थ कही जा सकती है। एमडीएमके की सामान्य परिषद ने पारित प्रस्ताव में आरोप लगाया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पर्दे के पीछे ऐसी राजनीतिक कवायद हुई, जिसका उद्देश्य अन्नाद्रमुक की सरकार बनवाना था।

टीएमसी बागी गुट की 47 पूर्व पार्षदों के साथ बैठक

ममता गुट ने शिकायत दर्ज कराई, कहा-पार्टी के नाम-सिंबल का गलत इस्तेमाल हुआ

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी गुट ने शनिवार को एक हफ्ते में दूसरी बार मीटिंग की। इसमें 47 पूर्व पार्षदों शामिल हुए। बैठक पूर्वी कोलकाता के टॉपसिया इलाके में हुई। इससे पहले 22 जून को न्यू टाउन में भी बागी गुट की बैठक हुई थी। दोनों बैठकों में टीएमसी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल किया गया, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं लगाई गई। इधर, ममता बनर्जी गुट की डोला सेन ने न्यू टाउन और प्रगति मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित करने के साथ बिना अनुमति बैठक करने का भी आरोप लगाया गया है।

दोनों गुटों ने रैली की अनुमति मांगी

21 जुलाई को शहीद दिवस पर होने वाली रैली के लिए ममता बनर्जी गुट और बागी गुट, दोनों ने कोलकाता के धर्मतला में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी है। ममता गुट का कहना है कि वह पिछले 33 वर्षों से वहीं रैली करता आ रहा है। वहीं, बागी गुट ने भी उसी जगह रैली करने के लिए आवेदन देने की बात कही है। हालांकि, अनुमति नहीं मिलने पर उसने वैकल्पिक स्थान पर कार्यक्रम करने का संकेत दिया है।

बागी गुट बोला- हम ही असली टीएमसी

बागी विधायक संदीपन साहा ने कहा कि उनकी ही असली तृणमूल कांग्रेस है। हमारे पास पर्याप्त संख्या है। हम विधानसभा में प्रमुख विपक्ष हैं। साहा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन हो चुका है और जल्द ही राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कोलकाता नगर निगम चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। इस साल दिसंबर में चुनाव हो सकते है। दरअसल, 8 जून को कोलकाता नगर निगम का बोर्ड भंग कर दिया गया था। इसके बाद सभी पार्षदों, चेयरपर्सन और मेयर-इन-काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रशासक को सौंप दी गई।

महुआ मोइत्रा बोलीं- जनादेश ममता के साथ

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पार्टी का सिंबल और जनसमर्थन ममता बनर्जी के नेतृत्व से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक, सांसद या पार्षद पार्टी छोड़ दें, इससे जनादेश नहीं बदलता। टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने 22 जून को टीएमसी की पैरलल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुना गया। बागी गुट ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का भी ऐलान किया था। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस-चेयरमैन बनाया गया। जबकि ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा जनरल सेक्रेटरी बने। विधायक अख्रुज्जमान अंसारी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऋतब्रत ने दावा किया कि यह पूरा अधिवेशन पार्टी संविधान के अनुरूप आयोजित किया गया।

इंदौर। बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर पुलिस ने रविवार को जन जागरूकता साइकिल रैली निकाली। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित यह रैली साइबर सुरक्षा अभियान के तहत निकाली गई, जिसमें बच्चों,युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। रैली पलासिया स्थित 'आई लव इंदौर' स्थल से शुरू होकर घंटाघर,उच्च न्यायालय,रीगल और राजवाड़ा होते हुए पुनः पलासिया पहुंची। रवाना करने से पहले प्रतिभागियों ने सामूहिक व्यायाम भी किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के.सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भावना नगर ऑनर किलिंग केस में 6 को उम्रकैद, 8 साल बाद सजा

गवाह मुकरने के बाद भी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया

इंदौर। शहर के चर्चित भावना नगर ऑनर किलिंग मामले में करीब 8 वर्ष बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने शनिवार को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी और घायल गवाह अपने पुराने बयानों से मुकर गए, लेकिन अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों का अपराध सिद्ध माना।विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने आरोपी अरुण भालसे, शिवराम भालसे, राहुल पंवार, सोनू दांगे, राजेश मोये और विशाल खेडेकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 307 के तहत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्रेम विवाह से नाराजी

अभियोजन के प्रभारी उप संचालक राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि भावना नगर निवासी रिंकी भालसे ने वर्ष 2018 में तेजकरण भालसे से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से रिंकी के परिजन नाराज थे। 26 जुलाई 2018 को आरोपियों ने तेजकरण को घर के नीचे बुलाकर बहन को भगाकर शादी करने को लेकर विवाद किया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने तेजकरण और उसके मित्र मोनू पर चाकुओं तथा लात-घूंसों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तेजकरण को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतक की पत्नी भी पलटी

मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी रिंकी भालसे और घायल गवाह मोनू राव अपने पहले दिए गए बयानों से पलट गए। मोनू ने अदालत में आरोपियों की पहचान करने से भी इनकार कर दिया। इसके बावजूद विशेष लोक अभियोजक आरती भदौरिया ने अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। अदालत ने इन साक्ष्यों और गवाहों की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए अभियोजन के पक्ष को स्वीकार किया और सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि आरोपियों ने न केवल तेजकरण की हत्या की, बल्कि उसके साथ मौजूद मोनू की भी हत्या करने का प्रयास किया था। इसी आधार पर अदालत ने सभी दोषियों को हत्या के साथ-साथ हत्या के प्रयास के अपराध में भी दंडित किया।

एजेंटी विवाद में 3 दिन में 5 बसों में तोड़फोड़, अवैध वसूली का आरोप

कार्रवाई नहीं होने पर बस संचालक पहुंचे पुलिस कमिश्नर के पास

इंदौर। शहर के छोटी ग्वालटोली, तिलक नगर, भंवरकुआं और संयोगितागंज थाना क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों के दौरान 5 बसों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने के बाद बस संचालकों में नाराजगी है। संचालकों का आरोप है कि पूरा विवाद बसों की एजेंटी को लेकर चल रहा है। दो अलग-अलग थानों में नामजद शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बस संचालक शनिवार को पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। देवास बस यूनियन और चौहान ट्रेवल्स के संचालक धर्मेंद्र चौहान ने पुलिस कमिश्नर को दिए आवेदन में बताया कि उनकी बसें देवास-इंदौर और इंदौर-इच्छापुर रूट पर संचालित होती हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून को राहुल सोनकर और उसके साथियों ने बस (एमपी41पी0815) के ड्राइवर और स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके बाद बस के भीतर भी तोड़फोड़ की गई।

घटना के समय स्टाफ ने तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी थी। बस संचालकों का कहना है कि इस घटना के बाद अगले 2 दिनों के भीतर करीब 4 अन्य बसों में भी इसी तरह तोड़फोड़ की गई। जिस समय ये घटनाएं हुईं, बसों में यात्री भी सवार थे। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। बस यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप

लगाया कि राहुल सोनकर के साथ कपिल नामक व्यक्ति भी एजेंट बनाने के नाम पर बस संचालकों पर दबाव बनाता है और अवैध वसूली का प्रयास करता है। इस संबंध में भंवरकुआं और तिलक नगर थानों में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

बस संचालकों ने पुलिस कमिश्नर से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर ने शिकायत सुनने के बाद पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

अनियंत्रित बस डंपर में घुसी, 6 घायल

इंदौर। अहमदाबाद से इंदौर आ रही यात्री बस रविवार सुबह चंदन नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का शिकार हो गई। जवाहर स्थित पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर फैली रेती से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं प्रकाश, शोभा, भूपेंद्र, रितु, दिलीप और घनश्याम नाथ सहित छह यात्रियों को मामूली चोटें आईं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चंदन नगर पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सड़क पर फैली रेती दुर्घटना का मुख्य कारण सामने आया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सड़क पर रेती कैसे फैली और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मामला दर्ज कर दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है।

आज से फिर खुलेगी छावनी अनाज मंडी

इंदौर। छावनी (संयोगितागंज) अनाज मंडी में हम्माल-तुलावटी, किसान संगठनों और मंडी प्रशासन के बीच कई दिनों से चल रहा विवाद सोमवार को सुलझ गया। प्रशासन के साथ हुई बैठक में किसानों और हम्मालों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मंडी सचिव ने बताया कि मंडी निरीक्षक दिलीप रायकवार को छावनी मंडी से हटाकर उड़नदस्ता में पदस्थ किया गया है। वहीं, अवैध कब्जों की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। हम्माल यूनियन के नेता राजू प्रजापत और किसान नेता बबलू जाधव ने इसे किसान-मजदूर एकता की जीत बताते हुए कहा कि संयुक्त संघर्ष से ही समस्याओं का समाधान संभव हुआ। प्रशासन के आश्वासन के बाद निर्णय लिया गया कि किसानों की सुविधा के लिए छावनी अनाज मंडी मंगलवार से पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित होगी, जिससे उपज की खरीदी, तुलाई और विक्रय कार्य बिना किसी बाधा के हो सकेगा।

नलों से गंदा पानी, लोगों में आक्रोश बढ़ा

इंदौर। राजमोहल्ला क्षेत्र की हरिजन कॉलोनी (वार्ड-70, जोन-2) में दूषित पेयजल आपूर्ति से रहवासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से नलों में मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है, जो पीने योग्य नहीं है। इससे जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। गंदे पानी के कारण लोगों को पीने के लिए निजी स्तर पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रहवासियों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि जलापूर्ति लाइन की जांच कर दूषित पानी की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सके तथा संभावित बीमारियों से बचाव हो सके।

स्टेडियम में गूंजा साइबर सुरक्षा का संदेश

इंदौर। साइबर अपराधों से बचाव के लिए इंदौर पुलिस का जन जागरूकता अभियान अब खेल मैदान तक पहुंच गया है। होलकर स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट मुकाबले के दौरान विशाल एलईडी स्क्रीन पर साइबर सुरक्षा संबंधी संदेश प्रसारित कर दर्शकों और खिलाड़ियों को सतर्क रहने की सीख दी गई। पुलिस उपायुक्त जोन-3 अभिषेक रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान यह पहल कराई। संदेश में लोगों को फर्जी कॉल, ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी, क्यूआर कोड ठगी, सामाजिक माध्यमों पर खाते हैक होने, भ्रामक लिंक और ओटीपी साझा करने जैसे साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए। साथ ही अपील की गई कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें और साइबर ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर सहायता संख्या 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

विरोध करने पर भाई को पीटा

इन्दौर। जिला अस्पताल के सामने महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके भाई के साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने बताया कि वह शुक्रवार रात 8 बजे सब्जी खरीद रही थी। उसी दौरान आरोपी उसका पीछा कर छेड़छाड़ करने लगा। इसी बीच महिला का भाई भी मौके पर पहुंच गया। जब भाई ने आरोपी की इस हरकत का कड़ा विरोध किया तो आरोपी किशोर ने उसके साथ मारपीट की। चंदन नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

निगम ने 100 किलो पॉलीथिन जब्त की

इंदौर। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने राजवाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से करीब 100 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग जब्त किए। नगर निगम ने व्यापारी प्रदीप भीमवानी पर 25 हजार रुपए का स्पॉट फाइन भी लगाया। निगम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि राजदीप कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट स्थित गोदाम से आसपास की दुकानों और सब्जी मंडी में प्रतिबंधित पॉलिथीन की आपूर्ति की जा रही है। शुक्रवार को जैसे ही व्यापारी गोदाम खोलकर माल निकालने पहुंचा,निगम की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की। जांच में प्लास्टिक टिफिन सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कैरी बैग बरामद हुए। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के निर्माण,भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान सीएसआई संजय घावरी, सहायक सीएसआई लाखन लोधी, राहुल वर्मा और रिमूवल विभाग की टीम मौजूद रही।

बदमाशों से चोरी के 5 मोबाइल जब्त

इंदौर। अन्नपूर्णा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को दबोच लिया है। बदमाशों से पांच मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, कुछ दिनों से मोबाइल लूट की शिकायत मिल रही थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों को पकड़ने टीम बनाई थी। टीम ने पूर्व में हुई घटना वाले स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर राहुल पिता गोपाल रावत निवासी विदुर नगर तथा संयम पिता राजेश मोर निवासी बापू घनश्याम दास नगर को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने मोबाइल स्नेचिंग की तीन वारदात करना कबूल किया। जांच में सामने आया कि आरोपी शौक और मौज-मस्ती के खर्च पूरे करने मोबाइल लूट की घटनाएं करते थे। वे बाइक से सुनसान इलाकों में घूमते और मौका मिलते ही राहगीरों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे।

अटाला मार्केट में फुटपाथ से सामान उठाने पर निगम टीम से विवाद हुआ

दोनों पक्षों में हाथापाई, टीम पर लेनदेन करने का आरोप लगाया

इंदौर। फुटपाथ से सामान उठाने पहुंची निगम की पीली गैंग से व्यापारियों की झड़प हो गई। विवाद के चलते दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। व्यापारियों ने निगम टीम पर लेनदेन का आरोप लगाया। बाद में सराफा थाने में दोनों पक्षों ने शिकायती आवेदन दिया है। शनिवार दोपहर निगम की पीली गैंग राजवाड़ा स्थित अटाला बाजार पहुंची। यहां कुछ व्यापारी फुटपाथ पर सामान रखकर बेच रहे थे। इस पर गैंग व्यापारियों का सामान उठाने लगी। पहले तो व्यापारियों ने गैंग की कार्रवाई का विरोध किया, बाद में जब गैंग नहीं मानी तो विवाद हो गया। सैकड़ों व्यापारी एकजुट होकर गैंग की कार्रवाई रोकने इकट्ठा हो गए। व्यापारियों का आरोप है कि निगम की रिमूवल टीम (पीली गैंग) कार्रवाई से पहले पैसों की मांग करती है, फिर रुपए लेने के बावजूद सामान जब्त करने और कार्रवाई करने से नहीं चूकती। यदि इस प्रकार की कार्यशैली जारी रही तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

सुपरवाइजर की अभद्रता

कई फुटपाथ विक्रेताओं और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान रिमूवल दल के सुपरवाइजर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनका कहना है कि अधिकारी ने गाली-गलौज करते हुए सामान जब्त किया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि वे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में, पारदर्शी तरीके से और सम्मानजनक व्यवहार के साथ की जानी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि गैंग के कुछ कर्मचारी तो मासिक पैसा लेते हैं, इसके बावजूद वे सामान उठा ले जाते हैं। सहायक पुलिस आयुक्त (सराफा) विजय तिवारी ने बताया कि फुटपाथ पर सामान रखने को लेकर निगमकर्मी और व्यापारियों का विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने शिकायती आवेदन दिया है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

जीवित महिला को कागजों में 'मृत' दिखाकर करोड़ों की जमीन हड़पी

13 रिश्तेदारों पर धोखाधड़ी का केस, बेटी ने असलियत खोजी

इंदौर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उनकी करोड़ों की पुश्तैनी कृषि भूमि हड़पने का आरोप उनके ही रिश्तेदारों पर लगा है। आरोप है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर महिला का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया और बाद में जमीन बेचकर रकम आपस में बांट ली गई। बिजलपुर निवासी द्रोपतीबाई चौधरी ने बताया कि उनके पति रणछोड़दास के निधन के बाद 14 एकड़ कृषि भूमि उनके नाम दर्ज थी। ससुराल पक्ष के कुछ रिश्तेदारों ने धोखे से कई कोरे और फर्जी दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। आरोपियों ने पुश्तैनी मकान भी बेच दिया, लेकिन उन्हें बिक्री की राशि में कोई हिस्सा नहीं दिया। जब उन्होंने अपने अधिकार की मांग की तो उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट की गई और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया।

बेटी ने खोजा फर्जीवाड़ा

द्रोपतीबाई की बेटी सुनीता ने जब सरकारी कार्यालयों से जमीन से जुड़े दस्तावेज निकलवाए तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि द्रोपती बाई को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दशार्या था। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण कराया और उनका नाम हटाकर पूरी जमीन अन्य लोगों के नाम कर दी गई। इसके बाद जमीन बेचकर आरोपियों ने राशि बांट ली। मामले में पुलिस ने कैलाश चौधरी, शंकर चौधरी, जगदीश चौधरी, प्रकाश चौधरी, विष्णु चौधरी, शांतिलाल चौधरी, राजन चौधरी, सदन चौधरी, पवित्रा चौधरी, पार्वती चौधरी, लखन चौधरी, मनोज चौधरी तथा रामू नागदावाला पर केस दर्ज किया है।

महाराष्ट्र से बहन से मिलने इंदौर आए भाई की हार्टअटैक से मौत

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया

इंदौर। सदर बाजार थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र से बहन के घर आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक रात में तबीयत खराब होने पर सोने चला गया था, लेकिन सुबह काफी देर तक नहीं जागा। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राहुल भारती (35) निवासी वाशिम, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, राहुल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दो दिन पहले इंदौर के जूना रिसाला में रहने वाली बहन प्रियंका से मिलने आया था। वह महाराष्ट्र में ऑटो पार्ट्स की दुकान पर काम करता था। परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात राहुल ने घबराहट की शिकायत की थी। इसके बाद वह सो गया। शुक्रवार सुबह काफी देर तक जब वह नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आनन-फानन में उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एमवाय अस्पताल रेफर किया गया था। शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

सिक्योरिटी गार्ड की मौत- इधर, एमआईजी थाना क्षेत्र में 43 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड प्रहलाद कुशवाह की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार प्रह्लाद रात में खाना खाने के बाद सोया था, लेकिन शनिवार सुबह काफी देर तक नहीं उठा। जगाने की कोशिश करने पर उसकी मौत की जानकारी लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रहलाद के दो बच्चे हैं। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

तीन दोपहिया वाहन से बीयर,100 पाव देसी शराब पकड़ी

अवैध शराब पर आबकारी का ताबड़तोड़ एक्शन

इंदौर। जिले में अवैध शराब के निर्माण,परिवहन और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने शनिवार को दो बड़ी कार्रवाई करते हुए बीयर, देसी शराब और तीन दोपहिया वाहन जब्त किए। जब्त मदिरा और वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 2.62 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया।

सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत बम्बई बाजार क्षेत्र के पलसीकर मेन रोड पर एक एक्टिवा की तलाशी में 24 बोतल किंगफिशर अल्ट्रा बीयर (15.6 बल्क लीटर) बरामद की गई।

आरोपी राजेश चौरसिया के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं भोई मोहल्ला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक अन्य एक्टिवा से दो पेटी बीयर जब्त की गई। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर बख्शी बाग में घेराबंदी कर बिना नंबर की जुपिटर से दो कट्टों में 100 पाव देसी प्लेन शराब (42 बल्क लीटर) बरामद हुई। इस मामले में दिलीप सिरवानी और सोनू रायकवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

महिला मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला, गला दबाया

महिला का उज्जैन में सिजेरियन हुआ था, फिर यहां भेजा

इंदौर। उज्जैन से गंभीर हालत में रेफर की गई एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद श्री अरबिंदो अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार आक्रोशित परिजनों ने महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की और कथित तौर पर उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया।

मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर डॉक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। अस्पताल के अनुसार रुखसाना (पत्नी शाहरुख मुल्तानी) का उज्जैन के एक निजी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर देर रात उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के प्रयास किए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने संबंधित थाने में शिकायत देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीन डॉ आरआर वावरे ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ नाईक ने बताया कि अस्पताल में प्रदेशभर से गंभीर मरीज रेफर होकर आते हैं और चिकित्सक हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मरीज को बचाया नहीं जा पाता। ऐसे मामलों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा चिंता का विषय बनती जा रही है।

संपादकीय

अब महाराष्ट्र में पेपर लीक

देश में प्रवेश और नौकरी के लिए पात्रता परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा का पेपर दो दिन पूर्व लीक होने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। इस घटना ने उन लाखों परीक्षार्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यह परीक्षा अब फिर से होगी, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद राज्य भर में कुल 1028 केंद्रों पर 28 जून को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 आयोजित करने जा रही थी। जिसमें कुल 4 लाख 28 हज़ार 122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 2 लाख 26 हज़ार 363 सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक, गोपनीय सूचना के आधार पर यह पता चला था कि 27 जून तड़के भिवंडी में कुछ व्यक्तियों को इस प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी थी। इसके चलते भिवंडी पुलिस ने उस स्थान पर छापा मारा। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को तत्काल सत्यापन के लिए बुलाया गया। जांच में पता चला कि जून 2026 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रश्न पत्र में इन लोगों के पास कुछ एक जैसे प्रश्न थे। इस संबंध में भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस घटना से शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों को धक्का लगा है। वैसे भी महाराष्ट्र पेपर लीक का एपीसेंटर बन कर उभरा है। मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा के पेपर भी इसी राज्य में लीक हुए थे और कुछ पेपर सेटर ने ही किए थे। उस मामले की जांच अभी चल ही रही है कि अब टीईटी पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। फर्क इतना है यह पेपर परीक्षा होने के दो दिन पहले ही लीक हुआ और इसमें तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। चिंता की बात यह है कि नीट 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा सभी सुरक्षा उपाय किए थे, फिर भी यह कांड हो गया। इस बीच टीईटी परीक्षा पेपर लीक पर राजनीति भी शुरू हो गई। राज्य की सत्तारूढ़ देवेंद्र फडणवीस सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी कांग्रेस ने इस सरकार को प्रश्नपत्र लीक करने वाली सरकार बताया है। बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं, जो लीक नहीं होता। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर लिखा 'एक और पेपर लीक हो गया। जनता को इसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मंत्री इसके लिए कभी जवाबदेह नहीं होंगे।' राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार) की महिला राकांपा प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे ने तंज किया कि सीएम फडणवीस सावधान रहें, कोई सीएम पद का हार गले में डालने के लिए उत्सुक है। उनका इशारा एकनाथ शिंदे की ओर था, क्योंकि पेपरलीक ठाणे जिले में हुआ है, जो शिंदे का प्रभाव क्षेत्र है। जाहिर है कि पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र सरकार कटघरे में है। राजनीतिक आरोपों को अलग भी रखें तो यह उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जो सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब पाले हुए थे। अब दूसरी बार परीक्षा आयोजित करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसका पेपर भी लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है।

भारतीय राजनीति का अध:पतन

नजरिया

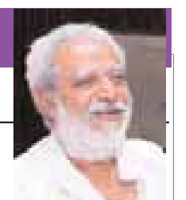

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

भारतीय राजनीति निरंतर पतन से अधःपतन की ओर बढ़ रही है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद सत्ताधारी कांग्रेस का नेतृत्व लगभग नियंत्रण मुक्त हो गया था। जो लोकप्रियता खोने के भय या सम्मान के चलते महात्मा गांधी की सलाह कुछ सुनी या मानी जाती थी उसकी भी संभावना समाप्त हो गई थी। 1952 के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिये कई प्रकार के अनैतिक उपक्रम शुरू किये। केरल की विरोधी सरकार को दलबदल कर गिराया और ऐसे कई प्रयोग कालान्तर में 1957 और 1962 के बाद कई सूबों में किये गये। श्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जिनके नाम से मंडल कमीशन जाना जाता है, वे बिहार के मधेपुरा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चुनकर आये थे और राज्य सरकार में मंत्री थे। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच दिया, सरकार गिराई गई और कुछ समय के लिये वे मंत्री बने और फिर उन्हें भी हटा दिया गया। बाद में वही श्री विंदेश्वरी मंडल 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय संगठन कांग्रेस याने मुरारजी कांग्रेस के साथ चले गये। उनके इन्हीं रिश्तों के चलते जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार से उपप्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मंत्रीमंडल से हटाया गया, तब उनके जनाधार को कम करने के लिये जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिये आयोग बनाने की बात स्वीकार की और जब वह आयोग बना तब उसका अध्यक्ष उन्हीं श्री वी.पी. मंडल को बनाया, जो पिछड़े वर्ग को धोखा देकर कांग्रेस के हाथ के खिलौना बने थे।

देश में दलबदल की शुरुआत कराने वाली भी कांग्रेस और उसके मुखिया थे। जहां कहीं भी प्रतिपक्ष का आधार बढ़ा उसे कमजोर करने के लिये कांग्रेस नेतृत्व ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाये। दल के भीतर रहकर, दल के निर्णय के खिलाफ्कार्य करने की परिपाटी भी कांग्रेस ने ही शुरू की थी। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस संगठन व सरकार के बीच गहरे मतभेद व टकराव थे। स्वरू जवाहर लाल नेहरू ने यह परिपाटी शुरू कर दी थी कि संगठन की तुलना में सत्ता सर्वोपरि है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में धीरे-धीरे सत्ता का केंद्रीयकरण किया इसके परिणामस्वरूप या तो संगठन को अप्रभावी बनाया या अपने कब्जे में ले लिया। स्वरू जवाहर लाल नेहरू के जीवनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थीं तथा वह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने लगी थी। राजनैतिक निर्णयों को करने के लिये स्वतः प्रधानमंत्री पार्टी के नेताओं को इंद्रा जी के पास जाने के इशारे देने लगे थे। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष, अलिखित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी प्रक्रिया को 1971 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया तथा अप्रत्यक्ष व अलिखित तौर पर सत्ता का नियंत्रक अपने बेटे संजय गांधी को बनाया था। 1969 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिये स्व. नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंद्रा गांधी उपस्थित थीं। उन्होंने न किसी नाम का प्रस्ताव किया और न कोई राय दी व चुप बैठी रहीं तथा बाद में वीवी गिरि को निर्दलीय तौर पर खड़ा कराया, उनका समर्थन किया, कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी को ऐनकेन प्रकारेण जिताया। कांग्रेस में अनुशासनहीनता की विधिवत और उच्च स्तरीय शुरुआत तो स्व. श्रीमती गांधी ने की थी। इसी प्रकार की अनेकों घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, उन्होंने पार्टी को व्यक्ति केन्द्रित या स्वः केन्द्रित बनाया। कांग्रेस के संगठन व ढांचे का विभाजन और पिछलग्गूपन यहीं से शुरू हुआ तथा महात्मा गांधी के जीवनकाल में जो परंपरा रही थी, कि सत्ता की तुलना में संगठन सर्वोपरि है, उस आदर्श परंपरा को मिटा दिया गया। इस व्यक्तिपरक और सत्तापरक सत्ता के प्रभुत्व के सिद्धांत की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी और अब धीरे-धीरे यह परिपाटी लगभग सभी पार्टियों में पहुंच चुकी है।

पार्टियों में अब अनुशासनहीनता वक्ती अपराध है याने चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा अब सबकी स्थिति विशेषतः संगठन की स्थिति दोयम दर्जे की है। जो लोग चुनाव का टिकिट नहीं मिलने पर, मंत्री नहीं बनने पर या मुख्यमंत्री नहीं बनने या हटाये जाने पर या केंद्रीय मंत्री नहीं बनाये जाने या हटाये जाने पर किसी सिद्धांत के लिये नहीं बल्कि स्वार्थों के लिये पार्टी छोड़ते हैं, दलबदल करते हैं और बाद में बहुमत में कमी रहती है तब उन्हें ही दलों की सत्ता व संगठन पर वापसी के नाम पर ससम्मान बुलाती और सत्ता में हिस्सेदारी देती है, जो कार्यकर्ता और विशेषतौर पर जमीनी कार्यकर्ता दल के नीति सिद्धांत से बंधे रहते हैं, उन दल बदलुओं को उनके ही सिर पर थोप दिया जाता है। याने कुल मिलाकर सिद्धांत यह हो गया है कि कोई भी दल हो उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के लिये जो भी अनैतिक कार्य करना हो वह करने को सत्ताधारी पक्ष तैयार रहता है। आजकल यह जुमला चल गया है कि भाजपा वाशिंग मशीन है और यह इसलिये कि जिन लोगों को भाजपा ने विपक्ष के रूप में भ्रष्टाचारी कहा, सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराये 100-200 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ के आरोप लगाये परंतु अपनी सत्ता बनाने के लिये उन्हें ही ससम्मान वापस लाकर पूरी पार्टी के सिर पर बैठा दिया गया। स्वरू अजीत पंवार को सरकार बनाने के लिये एनसीपी से तोड़कर उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, उनको निर्दोष सिद्ध करने के लिये सीबीआई केस वापस ले लिये गये और जब वे वापस एनसीपी में चले गये तो उसी सीबीआई ने बेशर्मी के साथ पुनः कार्यवाही की शुरुआत की। क्या सीबीआई के यह कार्य केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर नहीं थे? 2023 के विधानसभा चुनाव के समय फिर उन्हें मिलाया, फिर केस हटाया, फिर उपमुख्यमंत्री बनाया। याने जिन राजनैतिक अपराधों या राजैनतिक अनैतिकता की शुरुआत कांग्रेस ने अपने व्यापक राष्ट्र सत्ता के दौरान की थी उन्हीं तरीकों को और अधिक बेशर्मी के साथ भाजपा आगे ले जा रही है। हरियाणा में दलबदल का खेल छुटपुट चलता रहा परंतु स्व. देवी लाल जी को, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये श्री भजनलाल को जो कांग्रेस के थे, पूरे विधायकों के साथ जनता पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री बनाया गया। 1980 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और देवीलाल जी को लगभग बहुमत होने के बाद भी रोकने के लिये कि वह मुख्यमंत्री न बन सकें, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्रियों याने सारे मंत्री मंडल को वापिस कांग्रेस में शामिल करा दिया। क्या बिगड़ जाता अगर कांग्रेस एक दो राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को बर्दाश्त करती और अपनी पार्टी को नैतिक तरीकों से मजबूत बनाती।

नैतिकता के सिद्धांत को तो कांग्रेस ने पहले आम चुनाव के बाद ही त्याग दिया दिया था जब समाजवादियों ने कांग्रेस से निकलकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस के चिन्ह पर निर्वाचित विधायकों ने विधायक पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिये, तथा मध्यावधि चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े तथा अपनी ही पार्टी के पुराने साथियों को हराने के लिये कांग्रेस ने अनैतिक रास्ते अपनाये। यह सर्वविदित तथ्य है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी को हराने के लिये कांग्रेस ने बाबा राघवदास को खड़ा किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिये वोट मांगे। अगर आचार्य जी वह चुनाव जीत जाते, कांग्रेस पार्टी नैतिक मूल्यों का सम्मान करती और उन्हें हटाने के लिये हिंदुत्व कार्ड नहीं खेलती तो देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती तथा कटटरपंथ की राजनीति का उदय नहीं होता। आज कांग्रेस के ही अनैतिक व घिनौने अस्त्रों का इस्तेमाल, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। दुखद यह है कि 1950 से लेकर 1960 के दशक तक राजनीति व चुनाव में, पैसे का चलन उतना नहीं हुआ था। समाज में भी कमोवेश नैतिक मूल्यों का सम्मान होता था। चुनाव में पैसे का खुलकर उपयोग 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। उमा वासुदेव ने जिन्होंने उनकी आत्मकथा लिखी थी उसमें श्रीमती इंद्रा गांधी को एक प्रश्न के उत्तर में यह कहते हुये उद्धृत किया है कि 'मैं चुनाव इतने महंगे कर दूंगी कि कोई विरोधी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।' जिस राजनैतिक गंदगी की शुरुआत राजनीति में पैसे के चलन को कांग्रेस ने शुरू किया था अब उसी का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर भाजपा कर रही है। भाजपा को उद्योगपतियों ने इस वर्ष 6600 करोड़ रुपये का चंदा दिया और कांग्रेस को 1900 करोड़ का। याने अब भाजपा की सत्ता उद्योगपतियों को अधिक पसंद है बजाय कांग्रेस के। अब तो हालात इतने चिंताजनक है कि पंचायतों के चुनावों में लाखों से लेकर करोड़ों रुपया खर्च होने लगे। मतदाता पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में अपवाद छोड़कर सीधे रुपया लेकर वोट दे रहे हैं। जो लोग सीधे रुपया नहीं ले रहे हैं वे सरकार से कुछ हजार रुपये की सुविधाओं के बदले में वोट दे रहे हैं। यह भी लगभग उसी प्रकार वोट को बेचना है जिस प्रकार नगद रुपया देकर वोट को बेचना है। दिल्ली का उच्च मध्यमवर्ग और मध्यवर्ग जिसकी मासिक आमदनी औसतन लाख दो लाख प्रतिमाह से अधिक है, वह भी 200 यूनिट बिजली, 300 लीटर मुफ्त पानी, के लिये वोट देता है। अगर सामान्य व गरीब मतदाता 5-10 हजार रुपयों को लेकर अपना वोट बेचता है तो हमारा पढ़ा लिखा संभ्रांत मतदाता साल के 30-40 हजार रुपया और 5 साल के लिये लाख डेढ़ लाख रुपये में अपना वोट बेचता है। यह राजनीति के पतन का भयानक दौर है। पहले मुस्लिम मतदाता ने केवल कांग्रेस को वोट दिया, अपने मतों का ध्रुवीकरण किया और अब उसके प्रतिउत्तर में हिंदु मतदाताओं का ध्रुवीकरण शुरु हुआ तथा हिंदु मतदाता भी अब आमतौर पर भाजपा का समर्थक मतदाता बन रहा है। पहले कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराकर उनके वोट लेती थी, अब बहुसंख्यक हिंदु संप्रदाय को भाजपा डरा कर उनका भयादोहन कर रही है। दल बदल अब इतना फैल चुका है कि जो राजनीति व राजनैतिक दलों के लिये कैंसर जैसा हो गया है। अब जो पार्टी सरकार से हटती है उसके लोग बड़े पैमाने पर पार्टी को छोड़कर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं जो कि एक चलन बन गया है। जब प.बंगाल में कांग्रेस व सीपीएम सरकार से हटी तो कांग्रेस के काफी लोग ममता बनर्जी के साथ चले गये। और इस बार जब ममता बनर्जी हार गई तो चुनाव के दो माह भी नहीं हुए और उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक, सांसद, यहां तक कि राज्यसभा के सदस्य भी पार्टी छोड़कर चले गये। यह स्थिति करीब-करीब सभी सूबों में, सभी दलों के साथ हो रही है। जब कभी दिल्ली का ताज भाजपा से छिनेगा तो उनकी पार्टी में भी इससे ज्यादा भगदड़ मचेगी। राजनीति व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सत्ता का खून पीने की दाढ़ लग चुकी है और अब यह जल्दी रुकने वाली नहीं है। इसलिये भाजपा हर हाल में अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये हर अपराध करेगी, कानून को तोड़ेगी, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनायेगी और व्यक्ति केन्द्रित सत्ता की परिपाटी को चलायेगी।

मैं उन सभी लोगों से जो सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, अपील करता हूँ कि इस अनैतिकता की गिरावट, भयंकर आंधी और तूफान में भी आप तिनके के समान खड़े रहें। आंधी, तूफ़ान जायेगा परंतु ये तिनके ही कल राजनीति की नैतिकता के मार्गदर्शक और आधार बनेंगे।

नर्क से निपटते सीवर सफाई-कर्मी

सामयिक

कुमार कृष्णन

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

'बिहार के वैशाली में एक सेप्टिक टैंक के भीतर एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत,' 'छत्तीसगढ़ में रायपुर के एक अस्पताल के सेप्टिक टैंक में तीन कर्मचारियों की मौत,' 'मध्यप्रदेश के इंदौर में बचाव कार्य के दौरान सीवर कर्मचारियों की मौत,' 'दिल्ली के सीमापुरी में एक संविदा सफाई कर्मचारी की मौत, खुले नाले की सफाई के लिए मजबूर किया गया,' 'हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ठेकेदारों और नगर निकायों के सफाई कार्यों के दौरान हुई कई सीवर मौतें,' 'औद्योगिक ड्रेनेज टैंकों और सीवेज चैम्बरों में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के काम करते हुए प्रवासी मजदूरों की मौतें।'

सीवर- मौतों की ये खबरें उस समय आ रही हैं जब 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत खतरनाक 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' (मैला ढोने की कुप्रथा) पर कानूनी प्रतिबंध लागू है; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मशीनीकरण और मुआवजे को लेकर कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं; तथा सरकारें बार-बार 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' समाप्त करने के दावे करती रही हैं। भारत में, हाथ से मैला ढोने वालों की गरिमा और बुनियादी अधिकारों की लड़ाई अभी भी जारी है।

मार्च से मई 2026 के दौरान विभिन्न राज्यों से सामने आई सीवर और सेप्टिक टैंक मौतों की रिपोर्ट के मुताबिक तीन महीनों के दौरान ही कम-से-कम 36 सफाई कर्मचारियों की सीवर, सेप्टिक टैंक, नालों और सीवेज चैम्बरों की सफाई करते समय अत्यंत असुरक्षित और अवैध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक कर्मचारी मुख्यतः वाल्मीकि समुदाय और अन्य हाशिये के समुदायों या प्रवासी मजदूरों से थे तथा अधिकांशतः अनौपचारिक ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से कार्यरत थे।

इन लगभग हर मामलों में कर्मचारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्रीदिंग अपरेटस, गैस डिटेक्टर, सुरक्षा पोशाक, हार्नेस या आपातकालीन बचाव प्रणाली के बिना अत्यधिक जहरीले बंद स्थानों में उतरने के लिए मजबूर किया गया था। इन मौतों में एक ही भयावह ढ़ंग देखने को मिला, जो भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक मौतों में आम है-एक कर्मचारी चैम्बर में उतरता है और जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होकर गिर जाता है, उसे बचाने उसके सहकर्मी अंदर जाते हैं और वही असुरक्षित परिस्थिति उनकी भी जान ले लेती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना सीवर या सेप्टिक टैंक में नहीं उतरने और सीवर, सेप्टिक टैंक मौतों के लिए 30 लाख रुपये मुआवजे का निर्देश भी दिया है। इसके बावजूद यह प्रथा जारी है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि 2017 से 2026 की शुरुआत तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान 622 कर्मचारियों की मौतें हुईं। वर्ष 2021 से 2025 के बीच खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों में 317 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई; अप्रैल 2026 तक 'नमस्ते योजना' के तहत 89,248 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की गई।

ऐसी मौतों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक होती है क्योंकि अनेक मौतों को 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' की बजाय सामान्य दुर्घटना के रूप में दर्ज कर दिया जाता है। अनौपचारिक और आउटसोर्स ठेकेदारी व्यवस्था भी श्रम उल्लंघनों और मौतों को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' की निरंतरता गहरे जातिगत भेदभाव, श्रम शोषण, प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा मानकों के कमजोर क्रियान्वयन और सरकारों तथा नागरिक निकायों द्वारा बार-बार किए गए वादों के बावजूद मशीनीकृत सफाई व्यवस्था लागू न करने की विफलता को दर्शाती है। मृत कर्मचारियों के परिवारों को निश्चित समयसीमा के भीतर मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कई परिवार अंतिम संस्कार तक करने में असमर्थ होते हैं। सभी सीवर कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए और सरकार व प्रशासन को उनके कल्याण के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अधिवक्ता कवलप्रीत कौर के अनुसार 'दलित, आदिवासी शक्ति अधिकार मंच' की रिपोर्ट के अनुसार केवल तीन महीनों में 36 सीवर कर्मचारियों की मौतें हुई, यानी हर महीने औसतन 12 मौतें। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' और कई अदालती फैसलों के बावजूद ये मौतें जारी हैं। ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो कर्मचारियों को जानबूझकर मौत के कुएँ में उतरने के लिए मजबूर करती हैं?

ठेका प्रणाली में न तो नगर निकाय और न ही ठेकेदार कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। नियमित व्यवस्था में कम-से-कम राज्य जवाबदेह होता है। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा, इसे अदालतों ने बंधुआ मजदूरी का एक रूप माना है। सीवर कर्मचारियों को केवल न्यूनतम नहीं, बल्कि जीवन-निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए। चूँकि सीवर कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए सफाई कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए।

सीवर सफाई कर्मियों की मृत्यु पर 30 लाख रुपये और चोट लगने पर 20 लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक और जीवन-निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए। 'अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव पालीवाल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद भी सीवर कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को पीड़ितों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उनके पीछे परिवार हैं, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद गरीबी और बेबसी का जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कम-से-कम पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये परिवार अधिक पीड़ा न झेलें।

'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' तथा सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद पूरे देश में जारी 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' और खतरनाक सफाई कार्य गंभीर दीर्घकालिक शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जिनमें जहरीली गैस से दम घुटना, श्वसन रोग, त्वचा संक्रमण, मस्कुलोस्केलेटल विकार, न्यूरोलॉजिकल जटिलताएँ, डूबने का खतरा, मानसिक आघात, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, नशे की निर्भरता और जीवन प्रत्याशा में कमी शामिल हैं। इसके बावजूद व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी, नियमित चिकित्सीय जांच, बीमा कवरेज, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, मुआवजा और पुनर्वास सहायता लगभग अनुपस्थित हैं।

सफाई कर्मचारियों की लगातार मौतें भारत में जाति-आधारित संरचनात्मक हिंसा के सबसे गंभीर और स्थायी रूपों में से एक हैं। ये कर्मचारी कोई उपेक्षित मजदूर नहीं हैं। वे ऐसे इंसान हैं जिन्हें गरिमा, समानता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। 'दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच' ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर निकायों, न्यायपालिका, मानवाधिकार संस्थाओं तथा नागरिक समाज से अपील की है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को आजीविका कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरने के लिए मजबूर न होना पड़े। (सप्रेस)

नई पीढ़ी, स्वार्थ और संवेदनाओं का संकट

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तम्भकार हैं।

आज का समय विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता का युग है। हमारी नई पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, जागरूक और अवसरों से भरपूर है। फिर भी एक प्रश्न बार-बार मन को विचलित करता है कि सुविधाओं और संसाधनों की इस प्रचुरता के बीच मानवीय संवेदनाएँ क्यों कम होती जा रही हैं? क्यों आज कुछ युवा अपनी कुंठित इच्छाओं और क्षणिक भावनाओं के आगे इतने बेबस दिखाई देते हैं कि उन्हें अपने माता-पिता के प्रेम, त्याग और संघर्ष का मूल्य भी समझ में नहीं आता? माता-पिता अपने बच्चों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और हर परिस्थिति में बच्चों की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं। एक माँ रातों की नींद खोकर बच्चे का पालन-पोषण करती है और एक पिता अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन-रात परिश्रम करता है। किंतु दुख तब होता है जब वही बच्चे बड़े होकर केवल अपने स्वार्थ, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। उन्हें माता-पिता का प्रेम नहीं, बल्कि केवल अपनी सुविधाएँ दिखाई देती हैं।

समाज में आए दिन ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती हैं जहाँ संपत्ति, प्रेम संबंध, स्वतंत्रता या अन्य स्वार्थों के कारण युवा अपने ही माता-पिता के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। कभी-कभी तो वे ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिनकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सोचकर मन व्यथित हो उठता है कि जिन हाथों ने उन्हें चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को चोट पहुँचाने का साहस उनमें कैसे आ जाता है? क्या हमारी संवेदनाएँ इतनी कमजोर हो गई हैं कि रिश्तों का महत्व केवल तब तक रह गया है जब तक वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं?

आज की पीढ़ी के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव, त्वरित सफलता की चाह और सोशल मीडिया का प्रभाव उनके मन पर गहरा असर डाल रहा है। हर व्यक्ति दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, अधिक धन कमाना चाहता है और अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। जब इन इच्छाओं के मार्ग में कोई बाधा आती है, तब निराशा, क्रोध और कुंठा जन्म लेती है। धीरे-धीरे यह कुंठा व्यक्ति की सोच को इतना संकुचित कर देती है कि उसे सही और गलत का भेद भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज किसी को कष्ट पहुँचाना, अपमानित करना या उसके जीवन को नष्ट कर देना कुछ लोगों को आसान लगने लगा है, परंतु किसी के लिए त्याग करना, उसके लिए संघर्ष करना और उसके साथ खड़े रहना कठिन प्रतीत होता है। किसी का जीवन समाप्त कर देना एक क्षणिक आवेश का परिणाम हो सकता है, लेकिन किसी के लिए जीवनभर समर्पित रहना धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी की माँग करता है। शायद यही कारण है कि स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति आसान रास्ता चुन लेता है और मानवता का मार्ग छोड़ देता है।

प्रश्न यह नहीं है कि अपराध क्यों हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि ऐसी कौन-सी कुंठाएँ हैं जो हमें इतना घृणित कार्य करने पर भी झिझक महसूस नहीं होने देतीं? क्या यह संवेदनहीनता है? क्या यह आत्मकेंद्रित जीवनशैली का परिणाम है? या फिर यह परिवार और समाज में नैतिक मूल्यों के क्षरण का संकेत है? जब व्यक्ति केवल 'मैं' और 'मेरा' तक सीमित हो जाता है, तब उसके भीतर दूसरों के दुख को समझने की क्षमता कम होने लगती है। वह रिश्तों को भी लाभ और हानि के तराजू में तौलने लगता है।

इस समस्या का समाधान केवल कानून या दंड से नहीं हो सकता। इसके लिए परिवारों को संवाद बढ़ाना होगा, विद्यालयों को नैतिक शिक्षा और संवेदनशीलता पर अधिक ध्यान देना होगा तथा समाज को मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या स्वतंत्रता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों का सम्मान करने और दूसरों के लिए जीने में भी है।

अंततः यह समझना होगा कि मनुष्य की पहचान उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी संवेदनाओं से होती है। यदि हम अपने माता-पिता के प्रेम और त्याग का सम्मान नहीं कर सके, तो हमारी सारी प्रगति व्यर्थ है। नई पीढ़ी को यह याद रखना होगा कि किसी के लिए जीवित रहना, उसके सुख-दुख में सहभागी बनना और प्रेमपूर्वक संबंध निभाना ही सच्ची मानवता है। स्वार्थ और कुंठा के अंधकार से बाहर निकलकर हमें करुणा, कृतज्ञता और संवेदनशीलता के प्रकाश की ओर बढ़ना होगा, तभी एक स्वस्थ और मानवीय समाज का निर्माण संभव होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

भूमिका लिखने का लालच अभी रोके हुए है

व्यंग्य

डॉ.महेन्द्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

किसी भी नवोदित कवि/लेखक के साहित्यिक जीवन की सबसे बड़ी घटना उसके प्रथम संग्रह का प्रकाशन है। इसका उमंगदायी अनुभव वही जानते हैं जो इस दौर से गुज़रते हैं।प्रथम पुत्र की प्राप्ति जैसे अनिवर्चनीय आनंद को अनुभूत कर इतराना जीवन के दुर्लभ क्षणों में से एक है। पर किताब छपवाने की प्रक्रिया में उसे किसी वरिष्ठ नामचीन लेखक से भूमिका लिखवाना भी जरूरी हो जाता है जाकि उनके नाम के साथ उसकी भी पहचान बन सके। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे कुछ महत्वपूर्ण किन्तु गोपनीय बातों का ज्ञान होता है।एक तो यही कि लेखकों के अपने संगठन हैं और किताबों की भूमिका, समीक्षा या फ्लेप मैटर के लिए उनके संगठन से जुड़ना निहायत अनिवार्य है।

पिछले छह महीनों से भटक रहा तीन चार घाट का पानी पी चुका नवोदित सब तरफ से निराश होकर जब मुझ चतुर्थ श्रेणी साहित्यकार की शरण में अपने उददेश्य की पूर्ति के लिए आया तो मेरे व्यवहार से पसीजकर रोने लगा। तब उसने एक प्रथम श्रेणी साहित्यकार से वार्तालाप का जो ब्यौरा सुनाया वह ज्यों की त्यों प्रस्तुत है।कबीर की ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया की तरह।

चार महीने की प्रतीक्षा के बाद नवोदित ने उनसे संवाद स्थापित किया।हाय-हैलो कैसे हैं ? क्या चल रहा है ? क्या लिख रहे हैं ? के बाद बात सीधे पाण्डुलिपि की प्रस्तावना तक पहुंच गई।उसने झिझकते सकुचाते हुए निवेदन किया-सर, बहुत देर हो रही है अगर दो-तीन महीने और निकल गये तो किताब असामयिक, अप्रासांगिक हो जाएगी।

-हां !शायद, हो सकता है, क्या करें ? बताइये ?

-सर किताब तो पूरी तैयार है ,प्रेस में है आपका आशीर्वाद मिल जाता तो....

-हां,वो क्या है इधर कुछ काम ज्यादा है।

- आपके पास तो बहुत काम है सर,। मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दें। ..... उसने जब प्रार्थना लंबी खींचनी चाही तो उन्होंने उसे अनावश्यक मानकर स्विच ऑफ कर दिया।उसने दुबारा फोटोकॉपी कराकर, बातकर फिर एक वरिष्ठ का दामन पकड़ा। पूरी विनम्रता से उनसे भी भूमिका लिखने का अनुरोध किया।मना उन्होंने भी नहीं किया पर दो महीने बाद का वार्तालाप कुछ यूं थाः

-अरे भाई आपके ऊपर? मैं क्या लिखूंगा ? आपका इतना अच्छा काम है।

- आपका बड़प्पन है सर ,किताब पर आपका आशीष मिल जाए।

- ठीक है,ऐसा करो,यहीं आ जाओ बैठकर बात कर लेंगे।

-सर बात क्या ?आप जैसा कहें ।

-देखो मैं इधर व्यस्त हूं। कितना इंतज़ार कर सकते हो?

- सर इंतजार क्या,आप जैसा कहें।

ठीक है (अहसान जताते हुए) इसी महीने कोशिश करता हूं। हां ये बताओ कितने पेज की भूमिका ठीक रहेगी।

-सर जैसा आप उचित समझें।

-देखो ऐसी बात मत करो। मैं हज़ार रुपये फी पेज लेता हूं और तीन पेज से कम की भूमिका नहीं लिखता। और पेज बढ़वाना हो तो अभी बता दो, उन्होंने सारा बड़प्पन एक साथ कानों में उड़ेल दिया।

-जी सर! आप पाण्डुलिपि देख लें।'' मैं वहीं आ जाऊंगा।

-देखो आना-जाना अपनी जगह है।भूमिका लिखा लो और दो-दो पेज की दो तीन समीक्षाएं भी लिखा लो बाद में काम आएंगी। अब मैं पूरी किताब पढ़ूंगा,इतनी मेहनत करूंगा ।तुम्हारा काम भी एक साथ हो जाएगा। हां! समीक्षा भले किसी और के नाम से दे देना।मैं कुछ नहीं कहूंगा।ठीक है।

- मैं समझा नहीं सर ?

-क्या लिखते हो ? काम की बात भी नहीं समझते। कहते ही उन्होंने फोन काट दिया।

यह किस्सा सुनते ही मेरी समझदानी के किसी कोने में यह विचार जुगनू की तरह चमका कि वर्तमान साहित्य युगानुरूप अलग-अलग विचारधाराओं से अनुप्राणित अलग-अलग समूह के मुखियाओं की देखरेख में ही फल-फूल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद और अनुकंपा से उसे गति-सद्गति प्राप्त होती है। पारिश्रमिक चुकाने पर मनमाफिक गद्यात्मक उद्गार प्रस्फुटित होते हैं।आजकल सभी चाहते हैं कि लेखन में लगे समय का मेहनताना तो वसूल हो। ये सुनकर अब मन करता है साहित्यिक क्रिया-कर्म अब छोड़ दूं पर ऐसे में नई पीढ़ी की किताबों की भूमिका लिखने का लालच अभी रोके हुए है।

न्याय और कानून

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

'किशोर न्याय कानून' का उद्देश्य सुधार, सजा नहीं!

कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कानून से संघर्षरत बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण अंततः समाज के लिए ही विनाशकारी साबित होगा। किसी भी बच्चे के पुनर्वास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्य की अवधारणा की अधिनियम के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी उद्देश्य के अनुरूप समझा जाना चाहिए।

पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य कानून से संघर्षरत बच्चों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनका सुधार और पुनर्वास करना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपी अपराध की गंभीरता या किशोर की आयु जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी किशोर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हालांकि मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने विचारण न्यायालय का आदेश बरकरार रखते हुए अपील खारिज की। मामला भारतीय न्याय सहिता की धाराओं 103(1) और 61(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज हत्या के एक मामले से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार किशोर का नाम सह आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया। बाल न्यायालय ने सामाजिक जांच रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि किशोर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संगति में था, पढ़ाई छोड़ चुका था और नशे का आदी था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसकी पहचान परेड भी नहीं कराई गई। अधिनियम की धारा 12 में जमानत से इनकार के लिए निर्धारित कोई भी आधार इस मामले में मौजूद नहीं है।

वहीं, राज्य सरकार ने किशोर के आपराधिक रिकॉर्ड, सामाजिक जांच रिपोर्ट और यह तथ्य सामने रखा कि उसके माता-पिता झारखंड में रहते हैं तथा उसके लिए प्रभावी अभिभावकीय देखरेख उपलब्ध नहीं है। धारा 12 की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान सामान्य आपराधिक कानून में जमानत संबंधी प्रावधानों पर प्रभावी है। अधिनियम के तहत किशोर को जमानत देना सामान्य नियम है, जबकि जमानत से इनकार अपवाद है। न्यायालय ने कहा कि जमानत केवल तभी रोकी जा सकती है, जब रिहाई से बच्चे के ज्ञात अपराधियों की संगति में जाने, नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे में पड़ने अथवा न्याय के उद्देष्य प्रभावित होने की आशंका हो।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित अपराध की गंभीरता या किशोर की आयु, धारा 12 के तहत जमानत से इनकार करने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं है। यहां तक कि 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह किशोर, जिस पर जघन्य अपराध का आरोप हो, भी अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत पाने का अधिकार रखता है।'' न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम में प्रयुक्त न्याय के उद्देश्य की अवधारणा की अधिनियम के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी उद्देश्य के अनुरूप समझा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई भी समाज अपने बच्चों को दंडित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कानून से संघर्षरत बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण अंततः समाज के लिए ही विनाशकारी साबित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी बच्चे के पुनर्वास में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि प्रेक्षण गृह अधिनियम के तहत एक व्यवस्था है, लेकिन बच्चे की देखभाल, संरक्षण और समाज में पुर्नस्थापना के लिए परिवार सर्वोत्तम संस्था है। इसलिए प्रत्येक ऐसे बच्चे को यथाशीघ्र परिवार से मिलने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पाया कि किशोर पर हत्या के अलावा हत्या के प्रयास से जुड़े दो अन्य आपराधिक मामलों में भी आरोप हैं। सामाजिक जांच रिपोर्ट में उसके आपराधिक तत्वों की संगति और नशे की लत का भी उल्लेख है। साथ ही उसके लिए अनुकूल पारिवारिक वातावरण और प्रभावी अभिभावकीय देखरेख का अभाव भी सामने लाया। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि फिलहाल प्रेक्षण गृह में रहना ही किशोर के सुधार और पुनर्वास के लिए अधिक उपयुक्त होगा। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार करने का आदेश बरकरार रखते हुए अपील खारिज की। भारत में भी किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किशोर न्याय प्रणाली प्रचलित है। लेकिन, यह समझना भी आवश्यक है, कि यह सामान्य प्रणाली से अलग क्यों है और क्यों इस प्रकार के मामलों में कानून एक अलग रूख अपनाता है। हाल ही में एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि किशोर न्याय संबंधी याचिकाओं को प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि किशोर होने की प्रमाणिकता के लिए संदिग्ध प्रकृति के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आरोपी को किशोर नहीं माना जाएगा, यह देखते हुए कि यह कानून एक लाभकारी कानून है। किशोर अपराधियों (18 वर्ष से कम आयु) के किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 7-ए के तहत एक आरोपी व्यक्ति किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी स्तर पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी कर सकता है।

किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है। अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व संबंधी आयु प्राप्त नहीं की है और किशोर एक ऐसा अवयस्क है जिसने कोई अपराध किया है और उसे देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को 'डॉक्ट्रिन ऑफ डोली इनकैपैक्स' के कारण किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अपराध करने का इरादा रखने में असमर्थ व्यक्ति।

भारत में बाल अधिनियम, 1960 लागू किया गया। इस अधिनियम ने किसी भी परिस्थिति में बच्चों के कारावास को प्रतिबंधित किया और देखभाल, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, रखरखाव, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान किया। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, 1986 भी लागू किया गया। बाल अधिनियम को एकरूपता प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू किया गया, साथ ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1959 के अनुसार किशोरों की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित किए गए। सन् 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम को निरस्त कर एक नया अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लाया गया। इसमें कानून के साथ विवाद और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता जैसी बेहतर शब्दावली थी। जिन किशोरों का कानून के साथ टकराव होता है, उन्हें किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिन किशोरों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

हाल ही में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित किया गया। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मजबूत करने तथा कारगर बनाने का प्रयास करता है। न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबित है। न्यायालय की कार्यवाही में तीव्रता लाने के लिए अब शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया गया है। संशोधन में प्रावधान है कि इस तरह के गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार अब जिला मजिस्ट्रेट के पास है। इनके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम, 2013, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005 भी बालको एवं किशोरों के अपराधों के मामलों में प्रभावी है, ताकि बाल अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा ऐसी न हो जो उनका जीवन खराब करे।

संत कबीर जयंती

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

एक धोती और अनमोल सीख

संत कबीर को कभी किसी पर क्रोध नहीं आता था और यह बात दूर-दूर तक प्रचलित थी। एक बार बिगड़ैल किस्म के कुछ युवाओं को शरारत सूझी, जिनमें से एक लड़का तो बहुत धनी परिवार से था। सारे युवक कुछ योजना बनाकर कबीर को परेशान करने के इरादे से उनके पास पहुंचे ताकि वे अपनी हरकतों से कबीर को परेशान कर उन्हें गुस्सा दिला सकें। युवकों ने वहां पहुंचकर कबीर से एक धोती की इशारा करते हुए कहा कि यह धोती तुम कितने की दोगे? कबीर ने उत्तर दिया, '10 रुपये की।'

प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन संत कबीर दास जी की जयंती मनाई जाती है, जो 29 जून को मनाई जा रही है। संत कबीर अपने भजनों के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर किया करते थे। कबीर के दोहों, साखियों, पदों, शब्दों, रमैणियों तथा उनकी वाणियों में ऐसे कितने ही उपदेश देखे जा सकते हैं, जो धर्म और समाज के पाखंड को उजागर करते हैं। संत कबीर को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता भी इसी से ही मिली थी। आज भी उनके भक्ति गीत ग्रामीण, आदिवासी और दलित इलाकों में बहुत प्रचलित हैं। सही मायनों में कबीर दास न केवल एक महान संत थे बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। संत कबीर एक जुलाहे के रूप में कार्य करते थे और स्वभाव से बेहद शांत, नम्र तथा ईमानदार थे। उन्होंने अपनी ऊंची सोच-समझ से उस दौर में न जाने कितने ही लोगों का जीवन बदल दिया था। संत कबीर से जुड़ा ऐसा ही किस्सा बहुत प्रचलित है।

संत कबीर को कभी किसी पर क्रोध नहीं आता था और यह बात दूर-दूर तक प्रचलित थी। एक बार बिगड़ैल किस्म के कुछ युवाओं को शरारत सूझी, जिनमें से एक लड़का तो बहुत धनी परिवार से था। सारे युवक कुछ योजना बनाकर कबीर को परेशान करने के इरादे से उनके पास पहुंचे ताकि वे अपनी हरकतों से कबीर को परेशान कर उन्हें गुस्सा दिला सकें। युवकों ने वहां पहुंचकर कबीर से एक धोती की इशारा करते हुए कहा कि यह धोती तुम कितने की दोगे? कबीर ने उत्तर दिया, '10 रुपये की।'

धन-दौलत के घमंड में चूर युवक ने कबीर को परेशान करने के उद्देश्य से धोती के दो टुकड़े कर दिये और फिर धोती का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर पूछा, मुझे पूरी धोती नहीं चाहिए बल्कि आधी ही चाहिए, यह बताओ, तुम कितने की दोगे? कबीर ने शांतिपूर्वक कहा कि यह आधी धोती 5 रुपये की है। लड़के ने धोती के उस टुकड़े को भी दो हिस्सों में बांट दिया और फिर पूछा कि अब इसकी क्या कीमत है? कबीर अभी भी पूरी तरह से शांत थे और शांतिपूर्वक ही उन्होंने जवाब दिया, ढ़ाई रुपये। बिगड़ैल लड़का इसी प्रकार धोती के टुकड़े करता गया और धोती के ढ़ेर सारे

टुकड़े करने के बाद बोला कि अब यह धोती मुझे नहीं चाहिए, इसके ये टुकड़े मेरे किस काम के? संत कबीर ने बेहद शांत भाव से कहा कि बच्चों! धोती के ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, अब तो किसी के भी काम के नहीं रहे। इतना कुछ घटित होने पर भी शांतचित्त कबीर के मुख से निकले ये शब्द उस लड़के को शर्मिन्दगी का अहसास कराने के लिए काफी थे। शर्मसार स्थिति में लड़का कहने लगा कि मैंने आपका काफी नुकसान किया है, इसलिए मैं इस धोती का दाम आपको दे देता हूं। कबीर ने कहा कि जब आप लोगों ने धोती ली ही नहीं है तो मैं आपसे पैसे आखिर किस चीज के लूं? इस पर लड़के ने अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कितना अमीर हूं और वैसे भी तुम ठहरे गरीब, इस धोती का दाम चुकाने पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तुम इसका घाटा कैसे सहोगे? वैसे भी तुम्हारा नुकसान मैंने किया है तो इसका घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए।

संत कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम यह घाटा पूरा कर ही नहीं सकते। जरा सोचकर देखो कि इस धोती को बनाने में किसान का कितना श्रम लगा, तब जाकर कपास पैदा हुई। फिर मेरी पत्नी ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। उसके बाद मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती, जब कोई इसे पहनता और इसका उपयोग करते हुए इससे लाभ उठाता लेकिन तुमने तो इसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तुम्हारे दिए गए 10 रुपये से इस मेहनत का घाटा भला कैसे पूरा होगा? उनकी आवाज में अभी भी क्रोध अथवा आक्रोश के स्थान पर विनम्रता, दया और सौम्यता के भाव थे। अब तो संत कबीर को परेशान करने के लिए भद्दी शरारत करने वाला धनी परिवार का वह लड़का शर्म से पानी-पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह संत कबीर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। कबीर ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा कि बेटा, यदि मैं तुमसे इस धोती की कीमत ले लेता तो इन पैसों से मेरा काम तो चल जाता लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी का वैसा ही हाल होता जो इस धोती का हुआ। धोती एक नष्ट हो गई तो मैं दूसरी बना लूंगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी यदि ऐसे ही अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी बेहतर जिंदगी तुम कहां से लाओगे? मेरे लिए तुम्हारा पश्चाताप ही इस धोती से भी कीमती है। संत की कबीर की इस सीख ने उस बिगड़ैल युवक के जीवन की दिशा ही बदल दी। ऐसे थे महान संत कबीर दास जी।

मुद्दा

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, आस्था पर राजनीति क्यों?

अयोध्या की पावन धरती पर विराजमान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हुआ। मंदिर परिसर में हुई चोरी की घटना ने न केवल श्रद्धालुओं के मन को व्यथित किया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू हो चुकी है। यह बिल्कुल सही और आवश्यक कदम है। कानून को अपना काम करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपराध अपराध होता है, और मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हाथ डालना किसी भी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं किया जा सकता। लेकिन, इस घटना से कहीं ज्यादा चिंताजनक और विचारणीय वह 'शोर' है, जिसे देश का तथाकथित विपक्ष इस मुद्दे पर मचा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या अपराध की यह घटना इतनी बड़ी है कि देश की संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया जाए, या फिर इस शोर के पीछे कोई गहरा सियासी एजेंडा काम कर रहा है? अगर हम ईमानदारी से इस स्थिति का विश्लेषण करें, तो विपक्ष का यह अचानक जागा 'संवेदनशील' चेहरा साफ दिखाई देता है। देशभर के कोने-कोने में स्थित मंदिरों में अतीत में भी चोरियां हुई हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और समृद्ध मंदिरों से लेकर उत्तर और पश्चिम के अनेक प्राचीन मंदिरों तक, चोरियों की घटनाएं समय-समय पर प्रकाश में आती रही हैं। उन घटनाओं पर क्या विपक्ष ने कभी यह हंगामा मचाया था? क्या तब विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्म और आस्था की दुहाई दी थी? क्या उस समय उन्होंने संसद का कामकाज रोका था? जवाब है, नहीं। अन्य मंदिरों की चोरी पर विपक्ष की जो 'गहरी खामोशी' रही, उसकी तुलना में राम मंदिर की चोरी पर किया गया यह 'अति-उत्साह' और शोर, उनकी नियत पर सवाल खड़ा करता है।

यह चुनिंदा शोर इसलिए नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह राम मंदिर वहां बना है, जहां इसे लेकर दशकों से चली आ रही आस्था की लहर की जीत हुई है। विपक्ष यह भूल गया है कि आज जिस राम मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता का उन्हें अचानक रोना आ रहा है, उसी मंदिर के निर्माण के खिलाफ वे कभी सबसे आगे खड़े थे। इतिहास इतना भी पुराना नहीं है कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं के बयानों को भुलाया जा सके। वे लोग, जो कभी भगवान राम को 'काल्पनिक' बताते थे, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और जिन्होंने मंदिर निर्माण रोकने के लिए हर संभव कानूनी और राजनीतिक दांवपेंच खेले थे, आज अचानक राम मंदिर के सबसे बड़े रक्षक कैसे बन गए? जो लोग कभी मंदिर के अस्तित्व को ही मानने को तैयार नहीं थे, आज मंदिर में चोरी होने पर आस्था के सौदागर बनकर देश को ज्ञान दे रहे हैं। यह दोहरा चरित्र और राजनीतिक पाखंड अपने आप में बेनकाब हो चुका है। विपक्ष का यह कुत्सित प्रयास दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की एक नाकाम कोशिश है। राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ, जिसने एक नए

भारत के निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि भाजपा के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य पूरा हुआ, जिसने भारत की सभ्यता को नई पहचान दी है। चूंकि विपक्ष के पास न तो कोई विकास का एजेंडा है और न ही जनता के बीच कोई स्वीकार्य चेहरा, इसलिए वे हर उस मुद्दे को भगवान बनाकर राजनीति करते हैं, जहां भाजपा की छवि को धूमिल किया जा सके।

अयोध्या राम मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह देश-दुनिया में भारतीय आस्था और संस्कृति की पहचान बन चुका है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।

विपक्ष जानबूझकर इस चोरी की घटना को इतना तूल दे रहा है ताकि देश और दुनिया के सामने राम मंदिर की छवि को धूमिल किया जा सके। वे चाहते हैं कि श्रद्धालुओं के मन में मंदिर प्रशासन और वर्तमान सरकार के प्रति संदेह की भावना पैदा हो।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी जगह, जो आज वैश्विक पटल पर भारत की 'सॉफ्ट पावर' और आस्था का प्रतीक है, उसे राजनीतिक रोटी सेंकने का जरिया बनाया जा रहा है। विपक्ष की यह मानसिकता दर्शाती है कि उनके लिए आस्था कोई मायने नहीं रखती, उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता पक्ष को बदनाम करना है। वे राम को नहीं, बल्कि राम के माध्यम से नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष को यह समझना होगा कि राम किसी एक पार्टी या विचारधारा के मोहताज नहीं हैं। राम करोड़ों भारतीयों के हृदय में बसते हैं, और जनता इस क्षुद्र राजनीति को अच्छी तरह से समझ रही है। चोरी के आरोपियों को कानून सजा देगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन को भी चाहिए कि वे सुरक्षा व्यवस्था में चूक को सुधारें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। लेकिन जिस विपक्ष ने आज मंदिर की चोरी पर इतना हल्ला बोला है, उसे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए कि जब मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशे जा रहे थे, तब उनकी सोच कहां थी? जब श्रद्धालुओं ने दशकों तक संघर्ष किया, तब उनका साथ कौन दे रहा था? आज वही लोग, जो कभी राम मंदिर आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देते थे, आज मंदिर की पवित्रता की दुहाई दे रहे हैं। यह नैतिकता का कितना बड़ा पतन है, इसका अंदाजा आम नागरिक आसानी से लगा सकता है।

अंततः, सत्य और आस्था की जीत हमेशा होती है। राम मंदिर अपनी गरिमा और भव्यता के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चोरी की यह घटना एक आपराधिक घटना है, जिसे कानून सुलझा लेगा। लेकिन विपक्ष जिस राजनीतिक कालिख को आस्था के इस दीपक पर पोतने का प्रयास कर रहा है, वह उसकी अपनी राजनीतिक छवि को हमेशा के लिए दागदार कर देगी। विपक्ष को समझना होगा कि आस्था का अपमान और धर्म का सियासीकरण देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राम मंदिर की छवि धूमिल करने का यह कुत्सित प्रयास उल्टा विपक्ष के अपने चेहरे पर लगी कालिख को ही उजागर कर रहा है। समय आ गया है कि विपक्ष अपने इस दोहरे चरित्र और गिरी हुई राजनीति से बाहर निकले, अन्यथा इतिहास उन्हें उसी जगह याद रखेगा, जहां वे कभी राम को 'काल्पनिक' बताकर खड़े थे। कानून दोषियों को दंड देगा, लेकिन जनता का न्यायालय विपक्ष की इस गिरी हुई मानसिकता को पहले ही दंडित कर चुका है।

अंडर-13 ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन स्पर्धा विजेता शटलर ईशमित अरोरा ने देश के मानचित्र पर धार का बढ़ाया मान

ईशमित की उपलब्धि पर अपने लाड़ले का धार ने किया भव्य नागरिक अभिनंदन

धार, राजेश शर्मा। ऐतिहासिक धारा नगरी और बैडमिंटन मानों एक दूसरे के पूरक हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शटलरों की पौध पैदा करने वाली यह धरा बैडमिंटन खेल विधा में देश और दुनिया के मानचित्र पर है। तभी तो खेल जगत में धार को बैडमिंटन की नर्सरी कहा जाता है। इस धरा के कई नामचीन खिलाडियों ने अपने खेल कौशल और स्वर्णिम उपलब्धियों से इंटरनेशनल और नेशनल एरिना में देश और प्रदेश को गौरवांवित किया है। इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए शटलर ईशमित की अरोरा ने ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन स्पर्धा का खिताब जीत कर धार को झूमने का अवसर दिया है। धार जिला बैडमिंटन एसोसिएशन एवं धार लिटिल शटलर वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में राजा देवीसिंह हॉल में अपने लाडले ईशमित के नागरिक अभिनंदन से इस ऐतिहासिक धरा का इतिहास मानों झंकृत हो उठा हो...

मुख्य अतिथि कलेक्टर राजीव रंजन मीना थे। अध्यक्षता एसपी सचिन शर्मा ने की। विशेष अतिथि धार जिला बैडमिंटन एसो. के अध्यक्ष प. छोटू शास्त्री, धार लिटिल शटलर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष शरदचन्द्र निगम, एसो. के वरिष्ठ परामर्शदाता समाजसेवी पंकज जैन, कोच शमशेर सिंह यादव, कोच सुधीर वर्मा, समाजसेवी सुरेश गोयल, धार के गौरव शटलर ईशमित अरोरा, धार जिला बैडमिंटन एसो. के सचिव सलीम खान मंचासीन थे।

उपलब्धि पूरे जिले के बच्चों के लिए प्रेरणा है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है : एसपी

एसपी सचिन शर्मा ने कहा ''खेल युवाओं को सही दिशा देता है। बैडमिंटन जैसे खेल बच्चों में धैर्य, संयम, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक मजबूती विकसित करते हैं। मोबाइल और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर यदि बच्चे खेल को अपना साथी बनाएंगे तो वे अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक भी बनेंगे। ईशमित की उपलब्धि पूरे जिले के बच्चों के लिए प्रेरणा है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।'' जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री ने कहा ''धार हमेशा से बैडमिंटन की नर्सरी रहा है। यहां से कई खिलाड़ियों ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज ईशमित अरोरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में धार से और भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेंगे।''

समाजसेवी और डीडीबीए के संस्थापक पंकज जैन ने धार से बैडमिंटन की शुरुआत से आज तक के सफर को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत किया।

शरदचन्द्र निगम, कोच शमशेरसिंह यादव, सुधीर वर्मा एवं ईशमित अरोरा की माताजी शिखा अरोरा ने संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत एसो. के कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र जोशी, सुरेश परमार, राजीव जोशी, निमिश गोयल, भूपेन्द्र जोशी, विशाल पिपलोदिया, लखन नवासा, एड. संतोष जाट, डॉ. रफीक शेख, गोपाल खंडेलवाल, अंकित पटोंदिया, समीक्षा जैन, संगीता बारिया, अंतरसिंह यादव आदि ने किया।

कोच सुधीर वर्मा एवं शमशेर सिंह यादव को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ईशमित अरोरा का पुष्पमालाओं, शॉल एवं स्मृति चिन्ह एवं 21 हजार का चेक भेंट कर नागरिक सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा ने किया । आभार राजीव जोशी ने व्यक्त किया।

आज इन बच्चों के बीच आकर मुझे भारत का उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा है : कलेक्टर

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा ''आज इन बच्चों के बीच आकर मुझे भारत का उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा है। जिस उत्साह, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ ये खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेगे। खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की सबसे बड़ी पाठशाला है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो तो सफलता अवश्य मिलती है। प्रशासन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग करेगा।

स्थानीय किसानों को कॉफी उत्पादन से जोड़ें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कुकरू के कॉफी बागान का किया अवलोकन

बैतूल। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू स्थित कॉफी बागान का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कॉफी बागान के इतिहास, भू-गर्भीय परिस्थितियों एवं यहां उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉफी की खेती की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए स्थानीय किसानों को कॉफी उत्पादन से जोडने् पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉफी उत्पादन क्षेत्र के ग्रामीणों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कॉफी प्रोसेसिंग का कार्य कर रही ल-वॉन कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा कर कॉफी प्रोसेसिंग, विपणन एवं क्षेत्र में कॉफी उत्पादन के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि कुकरू में वर्ष 1944 में ब्रिटिश महिला फ्लोरेंस हेंड्रिक्स द्वारा कॉफी बागान की स्थापना की गई थी। यह कॉफी बागान लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और वर्तमान में क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं कृषि धरोहर के रूप में पहचान रखता है। इस दौरान कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुकरू में बुच पॉइंट का किया अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बैतूल प्रवास के दौरान रविवार को जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू स्थित बुच पॉइंट का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बुच पॉइंट से चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतीय श्रृंखलाओं और प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि कुकरु की वादियां प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर हैं और यहां का वातावरण मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि यह स्थल सूर्योदय दर्शन बिंदू व बुच पॉईन्ट के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थल का नाम बुच पॉइन्ट बैतूल जिले में 4 जनवरी 1962 से 4 जनवरी 1965 तक कलेक्टर रहे श्री महेश नीलकंठ बुच की स्मृति में पड़ा, इनकी धर्मपत्नी निर्मला बुच (म.प्र) राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव रही। इस स्थल से सूर्योदय के समय पवन चक्किया एवं प्राकृतिक वादियों के बीच सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, जो की एक अत्यन्त मनोरथ दृश्य बनता है। तलहटी में कोरकू जनजातीय बाहुल्य लोकलदरी नामक ग्राम है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य एवं सांसद दुर्गादास उइके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मप्र जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर सहित कलेक्टर उपस्थित थे।

हाई स्कूल मैदान का ओपन जिम और बास्केटबॉल कोर्ट उजाड़ने का आरोप, ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

पूर्व विधायक के प्रयासों से बनी करीब 35 लाख रुपये की खेल एवं व्यायाम सुविधाएं क्षतिग्रस्त

कांग्रेस पार्षदों ने दोषियों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की

मुलताई। नगर के हाई स्कूल मैदान में स्थित ओपन जिम एवं बास्केटबॉल कोर्ट को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अंजलि सुमित शिवहरे, निर्मला उबनारे कांग्रेस पार्षदों ने संदीपनी विद्यालय के हॉस्टल निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लाखों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने का आरोप लगाया है। पार्षदों ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है। महिला पार्षदों का कहना है कि, हाई स्कूल मैदान में पूर्व विधायक सुखदेव पांसे के प्रयासों से लगभग 10 लाख रुपये की लागत से स्थापित ओपन जिम को हॉस्टल निर्माण कार्य के नाम पर उखाड़कर एक ओर फेंक दिया गया। इस दौरान जिम के कई उपकरण टूट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सावधानी बरती जाती तो इन उपकरणों को सुरक्षित रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था। मामले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्षद अंजलि सुमित शिवहरे एवं निर्मला उबनारे मौके पर पहुंचीं। उन्होंने ओपन जिम की दुर्दशा पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिम नगरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर स्थापित किया गया था। प्रतिदिन सुबह-शाम बड़ी संख्या में युवक-युवतियां, विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाएं यहां व्यायाम करने पहुंचते थे। इस सुविधा के नष्ट होने से नागरिकों में भारी निराशा है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी पूर्व विधायक सुखदेव पांसे के प्रयासों से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहयोग से लगभग 24 लाख रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक बास्केटबॉल कोर्ट को भी निर्माण कार्य के दौरान उखाड़ दिया गया था। उनका कहना है कि कोर्ट के साथ लगे बास्केटबॉल पोल भी हटाकर फेंक दिए गए, जिनमें से एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। वर्तमान में उस आधुनिक खेल सुविधा के अवशेष तक ढूंढना मुश्किल हो गया है। पार्षदों ने कहा कि एक ओर सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए नई खेल सुविधाएं विकसित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पहले से उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं को ही नष्ट किया जा रहा है। बिना उचित योजना के करीब 35 लाख रुपये की खेल एवं व्यायाम सामग्री को नुकसान पहुंचाना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने मांग की कि इस नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार से कराई जाए तथा क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत कर उन्हें शीघ्र किसी उपयुक्त स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए।

इनका कहना है–

ओपन जिम के उपकरण उखाड़े जाने की जानकारी मिली है। सामग्री हटाने के दौरान कुछ उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं। सोमवार को संदीपनी विद्यालय के ठेकेदार को नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। क्षतिग्रस्त सामग्री के संबंध में नियमानुसार ठोस कार्रवाई की जाएगी।

– महेश शर्मा,
उपयंत्री, नगर पालिका मुलताई

कबीर साहेब प्रकट दिवस पर सतलोक आश्रम में हो रहे आयोजन

254 यूनिट रक्तदान, 55 जोड़ो का दहेज मुक्त विवाह, 5850 ने लिया देहदान का संकल्प

बैतूल। सतलोक आश्रम में संत रामपाल महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहेब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय विशाल महा समागम का आयोजन किया जा रहा है जिसका समापन आज सोमवार होगा। समागम में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दूसरे दिन आश्रम में कई परोपकारी और समाज कल्याण के कार्य किए गए। महासमागम की शुरुआत तीन दिवसीय अखंड पाठ के साथ हुई, जिससे पूरा आश्रम परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चौबीसों घंटे शुद्ध देशी घी से निर्मित भंडारा चल रहा है जिसमें मिष्ठान, सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल आदि का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही, मानव कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखते हुए आश्रम में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में संत रामपाल महाराज के अनुयायियों में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने जिला चिकित्सालय बैतूल की टीम को 254 यूनिट रक्त डोनेट किया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के 5850 अनुयायियों ने चिकित्सा विज्ञान और समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वेच्छा से देहदान के फॉर्म भी भरे।

बिना बैंड-बाजा और तामझाम के, मात्र 17 मिनट में हुए दहेज मुक्त विवाह– महासमागम में 55 जोड़े बिना किसी फिजूलखर्ची, दिखावे, बैंड-बाजे या बारात के सादगीपूर्ण तरीके से एक पवित्र रिश्ते में बंधे। यह विवाह पूरी तरह से दहेज रहित था। गुरुवाणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट के भीतर विवाह की यह अनोखी और सादगीपूर्ण रस्म पूरी की गई, जो आज के समय में फिजूलखर्ची और दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति है। आश्रम परिसर में कबीर साहेब जी सहित महापुरुषों के जीवन पर आधारित एक भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। 3422 श्रद्धालुओं ने बुराइयां त्यागने का संकल्प लिया और संत जी से निशुल्क नाम दीक्षा लेकर मोक्ष का वास्तविक मार्ग अपनाया। महा समागम का समापन भोग की वाणी के साथ आज होगा।

सीएम से मिलने कुकरू जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जिले के दौरे के दौरान रविवार को पुलिस ने युवा कांग्रेस के करीब दो दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल कुकरू जा रहे थे। वहां वे अपनी विभिन्न मांगों और स्थानीय मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। पुलिस ने उन्हें खेड़ी क्षेत्र में रोककर हिरासत में लिया और बैतूल ले आई। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुबह से ही खेड़ी क्षेत्र में तैनात था। साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही कार्यकर्ताओं का काफिला कुकरू की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वागदरे, सरफराज खान और प्रदीप कोकाटे सहित करीब दो दर्जन कार्यकर्ता शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, युवा कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी अभिषेक परमार बैतूल में संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर विरोध दर्ज कराने की योजना बनाई थी। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत वागदरे ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भू-माफियाओं का बोलबाला है।

सोहागपुर में मोहर्रम पर करीबन आधा सैकड़ा ताज़िए रखे गए

सोहागपुर। नगर में मोहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, कौमी एकता और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72, साथियों की कर्बला में हुई शहादत की याद में नगर के विभिन्न वार्डों से आकर्षक ताजिए निकाले गए। पुराने थाने के पीछे करीबन आधा सैकड़ा ताज़िए रखे गए। जिसमें क़ौमी एकता की मिसाल कायम करते हिन्दू परिवार के प्रह्लाद किरार अपने पूर्वजों की परम्परा को जीवित रखने के ताजिया निर्माण करते हैं। उक्त परिवार करीबन सौ सालों से ताजीया

बना रहे हैं। नगर की गंगा-जमुनी तहजीब के। कारण कई हिन्दू परिवार में लोभान छोड़ने एवं ताजिया देखने पहुंचे थे। वहीं डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौर, एसडीओ पुलिस संजू चौहान, तहसीलदार आर एस झरबड़े आदि ने पुराने पुलिस थाने में मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को जायजा लिया। इसी अवसर पर नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी ने ने शांति, आपसी भाईचारे और त्योहार की पवित्रता पर बेहद सारगर्भित उद्बोधन देकर तालियां बटोरीं।इसी अवसर पर मुस्लिम त्यौहार कमेटी अध्यक्ष वसीम खान ने एसडीओ पुलिस संजू चौहान,नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी, तहसीलदार आर एस जेई विजय धुर्वे आदि का शाल से स्वागत किया। सुबह ताजियों को पुराने थाने से जुलूस निकाल कर रघुवंशी पुरा स्कूल परिसर में रखे गए। जिसके दर्शनों के लिए सजातीय बन्धुओं, महिलाओं एवं बच्चों की खासी उपस्थित रहीं। मोहर्रम के कारण पुलिस ने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए थे।

हिन्दू साम्राज्य दिवस : हमारा भारत प्राचीन ऋषियों एवं महापुरूषों की परंपरा, ज्ञानियों, विज्ञानियों का देश रहा है : संघ विभाग घोष प्रमुख मनीष सहारिया

सोहागपुर। हमारा भारत प्राचीन ऋषियों एवं महापुरुषों की परंपरा,ज्ञानियों,विज्ञानियों, का यह देश रहा है। कभी प्राचीन काल में यह विश्व गुरु था इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था,शश्य श्यामला यह धरती थी ऋषियों की भूमि, अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि हमारे पूर्वजों की भूमि थी। देवताओं का और दानवों का संघर्ष आज का नहीं है यह प्राचीन काल का संघर्ष है जब जब भी आसुरी शक्ति ने धर्म को मिटाने का कार्य किया है तब तब ईश्वरीय शक्ति ने इस धरा पर जन्म लेकर धर्म की रक्षा की है।जब भी इस धरा पर पापियों ने अत्याचार किया है धर्म का नाश किया है तब तब इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतरित होकर इस देश की रक्षा की है ।पूर्व में शुभ निशुंभ दो राक्षसों ने जब अत्याचार किया तो इस धरा पर देवी ने प्रकट होकर उनका वध किया। मधु,कैटब ने जब धर्म को हानि पहुंचाने का कार्य किया तब श्री हरी विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनका वध किया ।सतयुग में हिरण कश्यप,जिसको अमृता का वरदान प्राप्त था जो न दिन में मर सकता था न रात्रि में ,ना आकाश में ना धरती में, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, ना पशु से न नर से,न ब्रह्मा की बनाई श्रष्टि से,लेकिन उसको भी श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध करके धर्म की स्थापना की। उक्त उद्गार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग घोष प्रमुख मनीष सहारिया ने पुराने थाने के पीछे हिन्दू साम्राज्य दिवस के अवसर पर कहें। इस अवसर पर उत्कृष्ट वेशभूषा में शिवाजी महाराज की वेशभूषा से सुसज्जित युवक एवं उनके सेवक खड़े थे,समाजसेवी कृष्णा पालीवाल, एवं संत

भूरेलाल कहार मंचासीन थे। आपने आगे कहा कि हम त्रेता की बात करें तो पुलस्त्य कुल में जन्मे रावण ने जब अत्याचार किया, साधु संतों को मारा उनका वध किया, तब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लेकर जंगल में भटक भटक कर सीता मैया की खोज करते हुए धर्म की की रक्षा के लिए इस राष्ट्र की रक्षा के लिए रावण को लंका के अंदर घुस के मारा और धर्म की स्थापना की इसी तरह यदि हम द्वापर युग की बात करें तो भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारकर धर्म की स्थापना की और आज कलयुग में हम यदि देखें तो जब मुगलों का अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था ,जब विधर्मी हिंदुओं के साथ मार काट कर रहे थे उन पर अत्याचार कर रहे थे तब ऐसे समय में महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में जीजा माता ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जन्म देकर एक भारत माता के वीर सपूत को जन्म दिया था जिसने बड़े होकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की मुगलों को धूल चटाने का कार्य किया। स्वाभिमान, संस्कृति ,स्वराज की स्थापना करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का आज की त्रयोदशी ज्येष्ठ शुक्ला माह के दिन उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दी गई,उनका राज्यभिषेक किया गया था। उसी के अवसर पर आज भारतवर्ष आज के दिन को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं जिनके बताएं रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास करते हैं ।कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शिवकुमार पटेल ने किया।आभार कार्यक्रम प्रभारी विशाल गोलानी ने व्यक्त किया।बौद्धिक सभा के पश्चात काली मंदिर परिसर से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शासकीय कन्या शाला, बिहारी चौक, कमानिया गेट ,श्री राम चौराहे से होते हुए पुनः काली मंदिर में आकर विर्सजित हुई। शोभायात्रा में दाऊदयाल सिंह व्यायामशाला अखाड़े के युवाओं ने तरह-तरह के करतब दिखाएं। शोभायात्रा आतिशबाजी जलाई गई। शोभायात्रा में भाजपा प्रदेश मंत्री राजो मालवीय,समाजसेवी कन्नू लाल अग्रवाल,कृष्ण पालीवाल, जीवन जी दुबे,जिला प्रचारक नरेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता शिव कुमार, पटेल,राघवेंद्र पटेल जनपद उपाध्यक्ष,कार्यक्रम संयोजक रितेंद्र राजपूत,प्रभारी विशाल गोलानी, सतपाल सिंह राजपूत,मंगल सिंह रघुवंशी,अभय खंडेलवाल, गणेश अहिरवार,अमित बिल्लोरे,पार्षद राकेश चौरसिया,मोहन कहार,अखिलेश मालवीय, प्रहलाद गढ़वाल,उदल रघुवंशी, माधव भावसार,मृणाल घरामी, राकेश गोस्वामी,हिमांशु गुर्जर बाबू मेहरा,लकी तिवारी, सौरभ कसेरा, प्रशांत मालवी,यश सोनी ,अमर सिंह, मनोज गोलानी ,अनंत तिवारी नितेश शर्मा,प्रकाश मंडल , उत्तम घरामि, मनोजीत हलदर, दिव्यांश मेहरा, निलेश शर्मा, मयंक मंडल,अर्जुन कुशवाहा मोहित कहार,शिवाजी महाराज के स्वरूप में ऋतिक मालवी, संजय मेहरा, रूपेश रघुवंशी, सागर रघुवंशी, अनंत तिवारी, अमित साहू आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

घोड़ाडोंगरी में कृषि आदान प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण

अनाधिकृत उर्वरक एवं जैविक खाद जप्त, एफआईआर की कार्रवाई

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर बैतूल डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक के मार्गदर्शन एवं समक्ष में दिनांक 26 जून 2026 को जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड घोड़ाडोंगरी अंतर्गत कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स काका बीज भंडार, बागडोना के प्रोपराइटर श्री बजरंग लाल अग्रवाल के स्वयं के अनाधिकृत गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गोदाम में मैसर्स मोनि मिनरल्स एंड ग्राइंडर्स (यूनिट-2), औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर (झाबुआ) द्वारा निर्मित एन.पी.के. 20:20:10 उर्वरक की 16 बोरी एवं NPK 12:32:06 उर्वरक की 05 बोरी कुल 21 बोरियां तथा मैसर्स मॉडर्न एग्रो जेनेटिकस लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-3, पीथमपुर (धार) द्वारा निर्मित उजाला बायो ऑर्गेनिक मैन्योर की 44 बाल्टियां बिना अनुज्ञप्ति में दर्ज कराए अनाधिकृत रूप से भंडारित एवं विक्रय हेतु रखी हुई पाई गईं। उक्त सामाग्री पर दर्ज MRP अनुसार कुल राशि 108000 है कि जब्ती की गई है। उक्त उर्वरकों एवं जैविक खाद के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए सामग्री को जप्त कर सहकारी समिति, सारनी की सुपुर्दगी में रखा गया। साथ ही संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की गई। उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक ने बताया कि प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पाई गई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित उर्वरक विक्रेता फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा एवं गुणवत्तायुक्त सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में कृषि आदान प्रतिष्ठानों में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में दिनांक गुरुवार को नेशनल स्किल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, हरदा में 'अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस' के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश/सचिव महोदय, चंद्रशेखर राठौर द्वारा ''नालसा डॉन स्कीम 2025'' की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से समाज, युवाओं और छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरूध्द जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होने नालसा (नशा पीड़ितो को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान कराया जाता है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1098 एवं सायबर अपराध हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की गई। उक्त शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को नालसा/सालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं-बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018, की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनके द्वारा नालसा डॉन योजना, 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए एवं नशे की लत से दूर रहना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी क्रम में बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, नालसा हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर-15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। उक्त शिविर में कोचिंग संचालक श्री नवीन राठौर, विद्यार्थीगण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे।

■ निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विनिर्माण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए संबंधित संचालकों से चर्चा की

कलेक्टर गुप्ता ने औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इकाइयों की उत्पादन क्षमता, मशीनरी, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार उत्पादों के विपणन तथा रोजगार सृजन की स्थिति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न विनिर्माण एवं उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए संबंधित संचालकों से चर्चा की। उन्होंने यह जाना कि इकाइयों में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है तथा तैयार उत्पादों का विक्रय स्थानीय बाजारों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं राज्यों में किस प्रकार किया जा रहा है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने उद्योग संचालकों को निर्देशित किया कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां जिले की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार हैं और इनके विस्तार से स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित कई इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिनमें बायो कोल, एम-सैंड, फ्लोर मिल, प्लास्टिक उत्पाद, दाल प्रसंस्करण, सोलर स्ट्रक्चर, सीडिंग ऑफ वेसल, आइसक्रीम निर्माण तथा बायोगैस ब्रिकेट्स निर्माण जैसी उत्पादन गतिविधियां शामिल हैं। कलेक्टर ने इकाइयों में उपलब्ध संसाधनों, निवेश, रोजगार की स्थिति एवं उत्पादन क्षमता का भी अवलोकन किया। उन्होंने उद्योग संचालकों को शासन की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने, उत्पादन में गुणवत्ता बनाए रखने तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि जिले में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, उत्पादन बढ़ाने तथा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने औद्योगिक इकाइयों को सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी ताकि बिजली की बचत के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र अपने-अपने ख्याति अर्जित कर सके उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु शासन द्वारा मुहैया काराई जाने वाली सुविधाओं को भी रेखांकित किया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आज भ्रमण के दौरान जम्बार बागरी, सहित शहर में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों का मौके पर जायजा लिया है।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने भैरूंदा सब जेल का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल ने भैरूंदा सब-जेल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जेल में नशामुक्ति एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उन्होंने बंदियों को नशामुक्ति के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नशे की लत जीवन को बर्बाद कर देती है एवं कई अपराध नशे के कारण होते हैं। उन्होंने बंदियों से कहा कि यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो पूरे मन से संकल्प लें। इस अवसर पर सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बंदियों को बताया कि यदि वे नशा छोड़ना चाहते हैं तो उनकी लत निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से छुड़ाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव उनकी मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने नालसा डॉन स्कीम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। शिविर में बंदियों के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई, बंदियों से स्वास्थ्य की जानकारी ली गई एवं संपूर्ण जेल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बंदियों की समस्याओं को सुना और यथोचित निराकरण भी किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्रीमती उषा तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

विशाल जनजागरूकता रैली निकालकर दिया नशामुक्ति का संदेश

हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर लिया गया नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प

सीहोर (निप्र)। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर 'नशा मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत सीहोर में जनजागरूकता रैली एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। यह जनजागरूकता रैली आवासीय खेलकूद संस्थान से प्रारंभ हुई और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से दूर कर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। नशे के विरुद्ध जनभागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर सभी को नशामुक्ति का संकल्प दिलाया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत

अभियान अंतर्गत 17 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अभियान के दौरान मिनी मैराथन, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट सहित अनेक जनजागरूकता गतिविधियां जिले की शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में आयोजित की गई थीं। रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल बैंड द्वारा आकर्षक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में समाजसेवी श्रीमती अरुणा सुदेश राय, श्री सुदीप प्रजापति, आवासीय प्राचार्य श्री आलोक शर्मा श्री अंकुर शर्मा, सुश्री ओम शांति, सहायक संचालक श्री महेश यादव सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और बड़ी संख्या में नागरिक शमिल हुए।

मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण बना प्रशासन

सीहोर (निप्र)। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सीहोर एवं नर्मदापुरम के जिला प्रशासन की तत्परता देखने को मिली है। नर्मदापुरम जिले के ग्राम रसूलिया निवासी ब्रेन हेमरेज से पीड़ित 83 वर्षीय बुजुर्ग श्री राम गोपाल टोकसे को तत्काल उच्च स्तरीय उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उन्हें नागपुर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। नर्मदापुरम जिला प्रशासन द्वारा सुबह सीहोर जिला प्रशासन से बुधनी के ट्रायटेंड स्थित हेलीपैड पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। इस सूचना पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय हो गया और मरीज के सुरक्षित आवागमन से लेकर हेलीपैड पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर की गईं। बुधनी तहसीलदार श्री ललित सोनी ने बताया कि प्रशासन द्वारा मरीज को नर्मदापुरम से बुधनी हेलीपैड तक सुगमता से पहुंचाने तथा हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस के संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समन्वय स्थापित कर पूरी प्रक्रिया को त्वरित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। सुबह लगभग 11 बजे श्री राम गोपाल टोकसे को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नागपुर के लिए रवाना किया गया, जहां उनका विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाएगा।

आंगनबाड़ी बच्चों का प्राथमिक शाला में एक्सपोजर विजिट आयोजित

हरदा (निप्र)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं पांचवीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के आंगनबाड़ी बच्चों को वर्ष में दो बार प्राथमिक शालाओं का एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हरदा शहरी क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र हरदा खुर्द-1 एवं हरदा खुर्द-2 के बच्चों का प्राथमिक शाला हरदा खुर्द में एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षक श्रीमती पूजा चौहान ने बच्चों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराया तथा प्राथमिक शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक श्री शिवनारायण देवड़ा ने बच्चों एवं अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस, पाठ्यपुस्तकें तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही विद्यालय में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर बच्चों ने कहानी एवं कविताएं सुनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती भारती भल्लावी, पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा गौर, पर्यवेक्षक श्रीमती पूजा चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारती एवं नीतू, सहायिकाएं ज्योति और अरुणा, प्राथमिक शाला की शिक्षिकाएं अंजलि बघेल, प्रमिला चार्वे, भारती वाइन, प्रतिभा चावड़ा तथा ज्योति सोनी सहित बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को स्वल्पाहार कराया गया तथा सुरक्षित रूप से उनके घर पहुंचाया।

ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन के लिए गठित होंगी जल समितियां

▶▶ ग्राम पंचायत स्तर पर होगा जल समितियों का गठन, ग्रामीणों की भागीदारी से होगा योजनाओं का संचालन

सीहोर (निप्र)। ग्रामीण नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जल समितियां गठित की जाएगी। ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और योजनाओं के सुचारू संचालन के उद्देश्य से इन समितियों का गठन किया जाएगा। नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की अनुशंसा एवं पंचायत की स्वीकृति के आधार पर जल समिति का गठन किया जाएगा। पेसा अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की अनुशंसा के आधार पर समिति गठित होगी।

यदि किसी ग्राम पंचायत में पूर्व से नल जल योजना के संचालन एवं संधारण के लिए कोई समिति गठित है, तो उसका पुनर्गठन नए नियमों के अनुसार किया जाएगा। समिति गठन का आदेश पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

जल समिति में सरपंच पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि पंचायत सचिव समिति के पदेन सचिव रहेंगे। ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता समिति के पदेन सदस्य होंगे। समिति में नामांकित सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होगी। ग्राम पंचायत के

प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को समिति में सदस्य बनाया जाएगा, जो संबंधित उपभोक्ता परिवार से होना आवश्यक होगा। समिति में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी 25 प्रतिशत रहेगी।

जल समिति में महिलाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। लगातार तीन बैठकों में बिना उचित कारण एवं सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। ऐसे सदस्य के स्थान पर नियमानुसार नए सदस्य के नामांकन की अनुशंसा ग्राम पंचायत को की जाएगी। जल समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजनाओं की निगरानी, संचालन और संधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे ग्रामीणों को नियमित एवं बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

खरी फाटक रोड स्थित न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान पर आकस्मिक जांच

घरेलू गैस सिलेंडर एवं उपकरण जप्त

विदिशा (निप्र)। तहसीलदार एवं संबंधित विभागीय टीम द्वारा खरी फाटक रोड स्थित काली मस्जिद के पास संचालित न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान संचालक श्री जलील मौके पर उपस्थित मिले और उनके समक्ष संपूर्ण कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर में एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर तथा गैस संबंधी कार्यों में उपयोग होने वाला पीतल का नोजल पाया गया। मौके पर लिए गए कथनों में दुकान संचालक ने बताया कि वह लगभग 10 वर्षों से उक्त दुकान का

संचालन कर रहे हैं तथा गैस स्टोव की मरम्मत, प्रेशर संबंधी सुधार कार्य और बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का कार्य भी किया जाता है। जांच टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया गया। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने घरेलू गैस सिलेंडर एवं पीतल के नोजल को नियमानुसार जब्त करते हुए जप्ती पंचनामा तैयार किया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई तथा दुकान संचालक द्वारा दो गैस पास पुस्तिकाएं प्रस्तुत की गई। सम्पूर्ण कार्रवाई का पंचनामा तैयार कर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा गैस सुरक्षा मानकों एवं एलपीजी के नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जांच एवं निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रखने की बात कही गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित घरेलू कार्यों के लिए करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या अनधिकृत गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को दें, जिससे दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जोखिमों को रोका जा सके।

एक घरेलू गैस सिलेंडर व पीतल का नोजल जप्त कर बनाया पंचनामा

तहसीलदार श्री अजय पाठक एवं नायब तहसीलदार श्री अजय वर्मा एवं फूड विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विदिशा नगर में न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर दुकान संचालक जमील के पास से एक घरेलू गैस सिलेंडर व पीतल का नोजल जप्ती की कार्रवाई करते हुए सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही निरीक्षण उपरांत पंचनामा भी बनाया गया है। जांच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक नग घरेलू गैस सिलेंडर राशि रुपये 2200 एवं 20 रुपये तथा एक नग पीतल का नोजल राशि रुपये 100 इस प्रकार कुल 2320 रुपए की सामग्री जप्त कर सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई है।

राइट क्लिक

असल चुनौती राम भक्तों के 'ट्रस्ट' को फिर से बहाल करने की है..

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में अंततः मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, एक और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को राम भक्तों के दबाव में पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे किसी पश्चाताप अथवा नैतिक अपराध का भाव नहीं दिखाई देता। इस बीच यूपी सरकार ने एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर चढ़ावा राशि गणना से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया है। लेकिन इस समूचे कांड के 'सरगनाओं' के खिलाफ किसी कार्रवाई की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि 'किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा।' हैरानी की बात यह भी है कि इतना कांड होने और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का पहली बार लिखित बयान आया है कि इस्तीफे मिल गए हैं और ट्रस्ट का सोने चांदी का हिसाब काफी कुछ ठीक है, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हे दंड दिया जाएगा। गोविंद गिरी अब तक चुप क्यों थे, यह भी जांच का विषय है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में सरकार, रामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर प्रबंधन की अग्नि परीक्षा राम मंदिर में करोड़ों राम भक्तों का 'ट्रस्ट' कायम रखने की है। अगर दिखावे के लिए शक के घेरे में रहे चंपत राय, डॉ.अनिल मिश्रा और गोपाल राव को उनके 'तपस्वी जीवन' का हवाला देकर छोड़ दिया गया तो सरकार और मंदिर प्रबंधन की मंशा पर ही सवाल खड़े होंगे। विपक्ष तो इसे राजनीतिक रूप से भुनाएगा ही, मंदिर पर से राम भक्तों का भरोसा अगर उठ गया तो वो फिर वापस लाना लगभग असंभव होगा। क्योंकि आरोपों के जो जवाब दिए जा रहे हैं, वह राजनीतिक ज्यादा हैं, बजाए राजधर्म का पालन सुनिश्चित करने के।

इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड की टाइम लाइन को देखें तो शुरू से लेकर अब नरेटिव लगातार बदलते दिख रहे हैं। पहले तो यह साबित करने की कोशिश हुई कि कहीं कुछ हुआ ही है। जिनका राम में ही भरोसा नहीं है, वो चढ़ावा चोरी की बात फैला रहे हैं। जब गड़बड़ी के सबूत मिलने लगे तो कहा गया कि कुछ छोटे कर्मचारियों की 'गलती' को बड़े और नियोक्ता पदाधिकारियों की निष्ठा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। या यूं कहें कि ऐसी गड़बड़ियों को लेकर शक करना भी अपने हिंदू होने पर ही संदेह करने जैसा है। जब एसआईटी ने चढ़ावा चोरी और चोरों की बदलती माली हैसियत के प्रमाण दिए तो कहा गया कि 'कुछ' लोग गड़बड़ हो सकते हैं। इसके लिए ट्रस्टियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर कहा गया कि जैसे ही गड़बड़ी का पता चला (जोकि सवा साल से बेखौफ चल रही थी, और जिसके तीन माह के फुटेज भी मिल गए) ट्रस्टियों ने खुद एसआईटी बनाने के लिए कहा। चढ़ावा चोरी की अवधि और एसआईटी गठन की मांग के दर्मियान यह खेल सवा साल तक क्यों, किसने और कैसे चलने दिया, यह असली जांच और दंड का मुद्दा है। जब यह भी साफ होने लगा कि 14 सदस्यीय ट्रस्ट को वास्तव में दो-तीन लोग ही चला रहे थे, बाकी ट्रस्टी को केवल मूक दर्शक थे, तो कहा जा रहा है कि ट्रस्ट को भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो के इस्तीफे हुए हैं, उनकी जगह नए चेहरे बिठा दिए जाएं। दूसरी तरफ जन दबाव लगातार बन रहा है कि कार्रवाई की पूर्णाहुति तभी समझी जाएगी, जब इस भारी घोटाले के लिए नैतिक और प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं होती। क्योंकि इन लोगों उन राम भक्तों का विश्वास तोड़ा है, जो न किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक संगठन में हैं।

तर्क यह भी दिया जा रहा है कि चंपत राय जैसे लोग तपस्वी हैं। उनकी एक (महा) 'त्रुटि' उनके जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी 'लापरवाह तपस्विता' किस काम की, जब मामला करोड़ों राम भक्तों की निश्छल आस्था से जुड़ा हो। जो खेल उनकी नाक के नीचे सवा साल से चल रहा था, उसकी जानकारी ट्रस्ट के महासचिव को न हो, इस पर तो कोई परम मूर्ख ही भरोसा कर सकता है। अगर उन्हें जानकारी थी तो तत्काल कार्रवाई में कौन सी बाधा थी? क्यों पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं हुई, क्यों चोरों को तत्काल मंदिर से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों खजाने की चाबियां एक ट्रस्टी के ड्राइवर के भरोसे थीं, इस सवालों के जवाब तो हर राम भक्त हिंदू पूछ रहा है। सवाल यह भी है कि जिम्मेदार पद पर तैनात कोई अपने अधीनस्थों पर अंधविश्वास कैसे कर सकता है? या तो उसने तपस्वी की माफिक आंखें मूंद ली हों या फिर खुद राम भक्ति में इतना लीन हो गया हो कि भीतर क्या चल रहा है, इससे कोई सरोकार न हो। हो सकता है कि आरोपी ट्रस्टियों ने चढ़ावे की पाई भी न ली हो, लेकिन चोरों को चोरी करने देते रहने की नैतिक जिम्मेदारी से कैसे बचेंगे? यह तो आपराधिक लापरवाही है और दंडनीय है।

ज्यों-ज्यों जांच और कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह नरेटिव कमजोर पड़ता जा रहा है कि हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। एक सुझाव यह भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर जम्मू- कश्मीर के 'श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड' की तर्ज पर नया राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें राज्यपाल ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा कुछ धर्माचार्य, हिंदू समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के जानकारी रिटायर्ड अधिकारी होते हैं। ट्रस्ट के संचालन और मंदिर प्रबंधन का संपूर्ण दायित्व सीईओ का होता है। कुछ सुझाव उन मंदिरों के ट्रस्ट अथवा प्रबंधन के भी हैं, जहां मंदिर प्रबंधन बेहतर ढंग से और भक्तों की आस्था के अनुरूप किया जा रहा है। अब देखना यह है कि केन्द्र और राज्य सरकार राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में क्या फैसला लेती है। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति की बात तो लगभग सभी मान रहे हैं। लेकिन 'चढ़ावा चोरी' के लिए जिम्मेदार एक और घटक यानी बैंक की भूमिका पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। चढ़ावा राशि की गणना और हिसाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अहम भूमिका है। लेकिन उसने अभी तक अपने कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की हो, यह सुनने में नहीं आया। लेकिन इस प्रकरण में तो बैंक कर्मी ही शामिल दिखाई देते हैं।

इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण कोण राजनीतिक है। श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड ने विपक्ष को बैठे-बिठाए मोदी योगी सरकार, भाजपा, संघ और विहिप को घेरने का एक ऐसा मुद्दा दे दिया है, जिसकी गूंज राम भक्तों के ह्रदय तक हो रही है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर चढ़ावा चोरी कांड में निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों के खिलाफ कठोर तो सभी संदेही आस्था के कठघरे में खड़े दिखाई देंगे। राम भक्तों के बीच यही संदेश जाएगा कि जब प्रभु श्रीराम के मंदिर में ही राम राज स्थापित नहीं हो पाया तो देश प्रदेश में कहां से आएगा? भाजपा और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों का यह जवाबी तर्क बोदा साबित होगा कि राम मंदिर को वो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो श्रीराम मंदिर के खिलाफ रहे हैं या जो कभी रामलला के दर्शन करने गए ही नहीं। शुचिता पर उठी उंगली को यह कहकर नहीं मरोड़ा जा सकता कि उंगली ही गलत आदमी की है।

इस पूरे मामले में एक सकारात्मक संकेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर है। देर से ही सही, लेकिन जिस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि वो इसे परिणति तक पहुंचाएंगे। अगर योगी यह कर सके या उन्हें करने दिया गया तो भाजपा के अंदर भी उन्हें पद से हटाने को लेकर चल रही कुश्ती के भी वो केसरी साबित होंगे। वैसे भी भाजपा ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले योगी को यूपी से हटाने की हिमाकत की तो इसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चढ़ावा चोरी कांड के दोषियों को कठोर दंड देना और राम मंदिर की व्यवस्थाओं में राम भक्तों का ट्रस्ट (विश्वास) फिर से कायम करना, योगी के लिए भी बड़ी चुनौती है। अपने पद को दांव पर लगाकर भी योगी अगर यह कर पाए तो उनकी प्रतिष्ठा राम भक्तों की नजर में कई गुना बढ़ जाएगी। देखना यह है कि अव्यवस्था के 'चंपत राय' पर सुव्यवस्था के 'संपत राय' कितने भारी पड़ते हैं?

भोपाल में बच्चों को पिलाई गई दो बूंद जिंदगी की

जिलेभर में 2710 बूथ, रेलवे ने बनाए 22 विशेष केंद्र, घर-घर और ट्रेनों तक पहुंचीं टीमें

भोपाल। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार (28 जून) को जिलेभर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। भोपाल जिले में करीब 3.32 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2710 बूथ बनाए गए हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने भी 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में 22 पोलियो बूथ एवं मोबाइल टीमें तैनात की हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी एवं निजी अस्पतालों के अलावा शॉपिंग मॉल, प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी पोलियो बूथ बनाए गए हैं, ताकि जिले से बाहर जाने वाले और यहां आने वाले प्रत्येक 5 वर्ष तक के बच्चे को दवा पिलाई जा सके। हाई रिस्क क्षेत्रों जैसे ईंट भट्टों, क्रेशर, निर्माण स्थलों और घुमक्कड़ आबादी तक पहुंचने के लिए विशेष मोबाइल टीमें गठित की गई हैं।

ये टीमें घर-घर और चिन्हित स्थानों पर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक दे रही हैं। इधर, पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने भोपाल, इटारसी, बीना, गुना, गंजबासौदा सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 22 पोलियो टीकाकरण बूथ स्थापित किए हैं। साथ ही विशेष मोबाइल टीमें झेलम

एक्सप्रेस, पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, राजकोट एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रा कर रहे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को चलती ट्रेन में ही पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। रेलवे कॉलोनियों और पैसेंजर ट्रेनों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि भारत के पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अभियान के पहले दिन ही अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर दवा अवश्य पिलाएं। वहीं रेल प्रशासन ने भी यात्रियों और रेल कर्मचारियों से अपने बच्चों को अभियान का लाभ दिलाने की अपील की है।

5 साल तक के सभी बच्चों को पिलाई दवा

जेपी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेश अहीरवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश वर्ष 2014 से पोलियो मुक्त है और पूरा देश भी पोलियो मुक्त है। हालांकि इस उपलब्धि को कायम रखने के लिए जरूरी है कि 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की दो बूंद दवा अवश्य पिलाई जाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। इसी अभियान के तहत अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले सभी बच्चों को भी पोलियो की दो बूंद दवा पिलाई जा रही है, ताकि पोलियो पर मिली जीत बरकरार रहे। डॉ. कमलेश ने कहा कि पहले पोलियो का खतरा इतना अधिक था कि लगभग हर इलाके में पोलियो से प्रभावित बच्चे या दिव्यांग लोग आसानी से दिखाई दे जाते थे। लेकिन व्यापक टीकाकरण अभियान की बदौलत अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इससे साबित हुआ है कि समय पर टीकाकरण से पोलियो और उससे होने वाली स्थायी विकलांगता को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब लोगों में जागरूकता काफी बढ़ गई है। अभिभावक स्वयं उत्साह के साथ अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने लाते हैं और बच्चे भी खुशी-खुशी इस अभियान में भाग लेते हैं।

आईआईटी के 11 छात्रों को मिला एक-एक करोड़ का पैकेज

मंदी के बीच बहुत बड़ी उपलब्धि, इसरो के पूर्व प्रमुख भी रह गए दंग

इंदौर। वैश्विक आर्थिक सुस्ती और आईटी सेक्टर में छंटनी के दौर के बावजूद आईआईटी इंदौर ने अपने इतिहास का सबसे सफल प्लेसमेंट सीजन दर्ज किया है। पहली बार संस्थान के 11 बीटेक छात्रों को एक-एक करोड़ रुपए सालाना से अधिक के पैकेज मिले हैं। वहीं, बीटेक के 93 प्रतिशत से अधिक छात्रों को डिग्री पूरी होने से पहले ही नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं। शनिवार को संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए डायरेक्टर प्रो. सुहास एस. जोशी ने बताया कि इस प्लेसमेंट सीजन में बीटेक छात्रों को अब तक 270 जॉब ऑफर मिले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन (मास्टर्स) के विद्यार्थियों को भी 108 ऑफर प्राप्त हुए हैं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों ने आईआईटी इंदौर के विद्यार्थियों की भर्ती की है।

रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां- प्रो. जोशी ने बताया कि संस्थान के शोध कार्यो का दायरा लगातार बढ़ा है। अब तक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में 10,700 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और 280 नई तकनीकें विकसित की गई हैं। उद्योग और सरकारी संस्थानों के सहयोग से आईआईटी इंदौर अब तक 900 स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट और 730 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है। संस्थान ने 275 से अधिक पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से 135 को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें अकेले पिछले एक वर्ष में 80 पेटेंट मंजूर हुए हैं।

अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं का हुआ उद्घाटन

14वें दीक्षांत समारोह के दौरान ही आईआईटी इंदौर में एएनआरएफ-पेयर सक्षम (स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सेलरेटिंग नॉलेज, हेल्थकेयर, एडवांस्ड मैन्युफेक्चरिंग एंड इनोवेशन मिशन) परियोजना के अंतर्गत स्थापित अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन प्रज्ञान इनोवेशन ट्रांजिट प्रयोगशाला में किया गया। इन प्रयोगशालाओं का उद्घाटन नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के पूर्व सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर तथा आईआईटी इंदौर के शासी मंडल के अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉ. के. शिवन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरे के दौरान, गणमान्य अतिथियों ने नवस्थापित अनुसंधान प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया तथा संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानांतरणीय अनुसंधान को सुदृढ़ करने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय अनुसंधान अवसंरचना विकसित करने के लिए आईआईटी इंदौर के प्रयासों की सराहना की।

कही-सुनी

साय सरकार के लिए निर्णायक होगा जुलाई का महीना

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

माना जा रहा है कि जुलाई का महीना छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के लये निर्णायक हो सकता है। 13 से 17 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र है। इसके बाद सरकार में उलटफेर की संभावना है। कहा जा रहा है कि तब तक राष्ट्रीय टीम भी बन जाएगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का नया स्वरूप सामने आ जाएगा। प्रदेश के नेता एंटीकम्बेंसी फैक्टर को दूर करने की कवायद में लगे हैं। इसके लिए मंथन और विमर्श लगातार चल रहा है। 18 जुलाई के बाद परिदृश्य साफ़ होने के आसार हैं। बिजली बिल में बढ़ोत्तरी और खाद की कमी सरकार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं तो कुछ भाजपा विधायकों की कार्यशैली भी बीजेपी की छवि पर असर डाल रही है। कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में सर्जरी कर नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। हल्ला है कि सरकार और संगठन में बदलाव करते वक्त नई पीढ़ी को ही तव्वजो दी जाएगी। सरकार और संगठन में पुराने विधायक या नेता को स्थान मिल पाने की गुंजाइश कम बताई जा रही है।

कौन बनेगा जल संसाधन का ईएनसी?

जल संसाधन विभाग के प्रभारी ईएनसी शंकर ठाकुर 30 जून को रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में विभाग में चर्चा चल पड़ी है कि अगला प्रभारी ईएनसी कौन होगा ? जल संसाधन विभाग के कोई भी मुख्य अभियंता फिलहाल ईएनसी की पात्रता नहीं रखते हैं। इस कारण सरकार को किसी एक मुख्य अभियंता को ही प्रभारी ईएनसी बनाना पड़ेगा। अभी महानदी परियोजना के मुख्य अभियंता मक्सी कुजूर का नाम प्रभारी ईएनसी के लिए आगे चल रहा है, पर दौड़ में हसदेव कछार के मुख्य अभियंता जितेंद्र कुमार नेताम,हसदेव गंगा कछार के मुख्य अभियंता अनिल कुमार खलखो,महानदी गोदावरी कछार के मुख्य अभियंता सतीश कुमार टीकम और गोदावरी कछार के मुख्य अभियंता एलेक्जेंडर ग्राहम भी हैं। 30 जून को ही मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के मुख्य अभियंता शंकर राव सोनाने भी रिटायर हो रहे हैं। सरकार को वहां भी मुख्य अभियंता की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। विभाग में इन पांच अफसरों के अलावा कोई चीफ इंजीनियर नहीं हैं, इस वजह से कहा जा रहा किसी वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता का प्रभार दे दिया जाय। ईएनसी और एक चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग के चलते जल संसाधन विभाग में जुलाई महीने में बड़ा बदलाव हो सकता है।

जेब भरने में लगे हैं जल संसाधन के एसई साहब

कहते हैं जल संसाधन के एक अधीक्षण अभियंता (एसई) रिटायरमेंट के पहले जेब भरने में लगे हैं। बताते हैं साहब एक-दो महीने के भीतर ही रिटायर होने वाले हैं। जाते -जाते साहब सब कुछ समेट लेना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि एसई साहब हर फाइल और हर काम के लिए चढ़ावा चाहते हैं। एसई साहब की डिमांड से त्रस्त होकर ठेकेदारों ने तो कन्नी काट ही ली है, उनके मातहत अफसरों ने भी फाइल भेजना बंद कर दिया है। अफसर और ठेकेदार एस ई साहब के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा है कि एस ई साहब विभाग के एसडीओ से अंडर गारमेंट तक भी खरीदवाने से नहीं चूकते।

मंत्री जी का दिल्ली चक्कर

कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी पिछले एक महीने में कई बार दिल्ली का चक्कर लगा आए। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी सरकारी काम से दिल्ली का चक्कर लगा रहे या फिर संगठन के काम से। सुनने में आ रहा है कि अपने दिल्ली दौरे में मंत्री जी एक-दो बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाक़ात की। नितिन नबीन जल्द ही अपनी टीम बनाने वाले हैं। नितिन नबीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं, ऐसे में मंत्री जी पुरानी जान-पहचान के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले या फिर कोई और कारण है, यह चर्चा में है। हल्ला तो यह है कि विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का एक सदस्य नितिन नबीन जी की टीम में जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन राष्ट्रीय टीम में जाता है, या फिर यह केवल शिगूफा है।

कहाँ अटक गई आईपीएस की लिस्ट?

लंबे समय से आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। आमतौर पर जून महीने में आईपीएस अफसरों की एक तबादला लिस्ट आती ही है। कई जिलों में एसपी ढाई-पौने तीन साल से जमे हैं। इस कारण कई जिलों के एसपी में हेरफेर की अटकलें लगाई जा रही है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ के एसपी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने के कारण जिला खाली हो गया है। बलौदाबाजार-भाटपारा जैसा संवेदनशील जिला प्रभारी एसपी के भरोसे चल रहा है। सरकार ने आईपीएस सुंदरराज पी. के केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने के कारण बद्रीनारायण मीणा को बस्तर आईजी बना दिया। बद्री मीणा पहले भी कई रेंज में आई जी रह चुके हैं। चर्चा है कि कई जिलों में समीकरण नहीं बैठ पाने के कारण एसपी की तबादला सूची लटकी है। बाजार में एसपी की पोस्टिंग के लिए रेट भी तैर रहे हैं। एक औद्योगिक जिला मुख्यालय के एसपी के लिए सात खोखा, तो एक संभागीय मुख्यालय के एसपी के लिए तीन खोखा की चर्चा गर्म है।

उमेश पटेल से राहुल की चर्चा के मायने क्या ?

कहते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खरसिया के विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल से अकेले में चर्चा की। कांग्रेस हलकों में इस चर्चा के मायने अलग-अलग निकाले जा रहे हैं। उमेश पटेल नक्सली हिंसा में शहीद नंदकुमार पटेल के पुत्र हैं। नंदकुमार पटेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते शहीद हुए। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को तीन साल हो गए हैं, तो नए प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है। राहुल गांधी से चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए उमेश पटेल का नाम उछलने लगा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी उमेश पटेल का नाम सामने आया था, पर डॉ चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बने। वैसे प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव भी शामिल बताए जाते हैं। पर कुछ लोगों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष ओबीसी हैं तो कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी आदिवासी नेता पर ही दांव खेलेगा।

मंत्रियों के टारगेट में तीन अफसर

कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने 18 जून की बैठक में तीन अफसरों को निशाने पर लिया और उनकी बात न सुनने की शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय से की। बताते हैं कि तीन अफसरों में दो आईएएस और एक आईपीएस हैं। 18 जून को मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों की आकस्मिक बैठक बुलाई थी, जिसमें अजय जामवाल और पवन साय भी मौजूद थे।

कुछ कलेक्टर बदलने की हवा

कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में चार-पांच जिलों के कलेक्टर बदल सकते हैं। चर्चा है कि इस फेरबदल में कई बड़े जिले प्रभावित हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर और कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर इधर से उधर हो सकते हैं। कलेक्टरों के साथ मंत्रालय स्तर पर भी छोटा बदलाव हो सकता है।